सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-24 23 दिसम्बर, 2018 से 6 जनवरी 2019 मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति के परचम को बुलंद करने के लिए आज जरूरत है हजारों खुदीराम, भगत सिंह, अशफाकउल्ला खान, प्रीतिलता जैसे बहादुर क्रांतिकारियों की

जमशेदपुर में आयोजित खुले अधिवेशन में कॉमरेड प्रभास घोष

(26 नवम्बर 2018 को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के तीसरे अखिल भारतीय महासम्मेलन का खुला अधिवेशन जमशेदपुर के जी टाउन क्लब मैदान में आयोजित हुआ। उस विशाल सभा में मुख्य वक्ता के रूप में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) महासचिव कॉ. प्रभास घोष ने बांग्ला में सारगर्भित भाषण दिया। हम यहां कॉ. प्रभास घोष के उक्त भाषण का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं। अनुवाद संबंधी किसी भी त्रुटि-खामी की जिम्मेदारी हमारी होगी।
–सम्पादकमंडल, सर्वहारा दृष्टिकोण।)

कॉमरेड अध्यक्ष, कामरेड्स और मित्रो,

आपने सुना कि महान मार्क्सवादी चिंतक कॉ. शिवदास घोष द्वारा स्थापित एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की तीसरी कांग्रेस का प्रतिनिधि अधिवेशन 21-25 नवंबर 2018 को घाटशिला में आयोजित हुआ। आज 26 नवंबर 2018 को जमशेदपुर में उसका खुला अधिवेशन है। आप जानते हैं कि देश की बड़ी बुर्जुआ पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी पार्टी मसलन सीपीआई, सीपीआई (एम) और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां अगले लोकसभा चुनाव के समर में कूद पड़ी हैं। इस बात के कयास लगाये जा रहे हैं कि केन्द्र की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, कौन लोग दिल्ली की अपनी कुर्सी की हिफाजत कर पायेंगे और किसे, कहां, कितनी सीटें मिलेंगी। रोज अखबार और टीवी इन दलों के नेताओं के भाषण, उनकी उपलब्धियों के दावों और उनके वायदों का खूब प्रचार कर रहे हैं। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में कॉ. शिवदास घोष की शिक्षा के आधार पर हमने पार्टी कांग्रेस में चर्चा की कि निर्मम पूंजीवादी दमन-उत्पीड़न की चक्की में पिस रहे मजदूर-किसान तथा मध्यम वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को लेकर कैसे वर्ग संघर्ष और जन आन्दोलन विकसित किये जायें और कैसे उसी प्रक्रिया में आने वाले दिनों में पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति की तैयारी की जाये। इस मकसद से हमारी पार्टी को वैचारिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक और नीति-नैतिकता संबंधी हर तरफ से और कितना ताकतवर बनाया जा सकता है, यही था हमारी चर्चा का विषय। हमारी पार्टी चुनाव आधारित पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है। हमारी पार्टी का मानना है कि चुनाव के जरिये जनता की मौलिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉ. शिवदास घोष विचार की सीख है।

खुले अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए पार्टी के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष

देश की खौफनाक तस्वीर

सन् 1952 से आज तक अनेक संसदीय चुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ बहुत दिनों तक राज किया। भाजपा भी 'अच्छे दिन' का वादा करके सत्ता में आयी है। इसका नतीजा क्या हुआ, आप अपने कड़ुवे अनुभव से अच्छी तरह जानते हैं। आप रोजाना असह्य दुख-कष्टों को झेल रहे हैं। ये तमाम पार्टियां दावा करती हैं कि उनके शासन में देश की काफी तरक्की हुई है, काफी विकास हुआ है तथा आगे और भी होनेवाला है। मगर देश की तस्वीर क्या कहती है? हालांकि आप अपने अनुभव से देश की इस वस्तुनिष्ठ स्थिति से परिचित हैं, मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य और आंकड़े पढ़कर सुनाऊंगा। ये तथ्य और आंकड़े हमने मुहैया नहीं कराये हैं। ये तथ्य और आंकड़े विभिन्न सरकारी और प्रामाणिक गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। मात्र दो साल पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों

(शेष पृष्ठ 2 पर)

फ्रांस के शासकों के खिलाफ संघर्षरत वहां की जनता का अभिनंदन!

उनके साहस, उनकी एकता का अभिनंदन!

मानव जाति को डेमोक्रेसी की धारणा से अवगत कराने वाली फ्रांसीसी क्रांति की भूमि, 1968 के जबरदस्त छात्र आंदोलन की भूमि जिसने देश के तत्कालीन उत्कृष्ट बुद्धिजीवियों समेत विभिन्न सामाजिक स्तरों के लोगों को अपनी ओर खींचा था और दुनिया को हिला कर रख दिया था, जनता के बहुत से अन्य शानदार आंदोलनों की भूमि फ्रांस की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरी है। ये लोग जीवन के हर तबके से थे। इनमें मजदूरों, किसानों, ऑफिस कर्मचारियों, छात्रों के साथ शहरों, कस्बों गांवों से आईं गृहिणियां भी शामिल थीं। वे झुंड के झुंड हजारों और लाखों की संख्या में जुटे थे। इनमें वे मजदूर शामिल थे जो अनिच्छुक समझौता परस्त ट्रेड यूनियन नेतृत्व की अवहेलना करके आए थे और न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर भारी संख्या में शामिल हुए थे ताकि दो वक्त की रोटी मिल सके। वे वि-औद्योगिकीकरण का शिकार बने थे जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक मुनाफे के लिए दूसरे कम विकसित देशों में जाने को प्राथमिकता दे रही हैं, जहां श्रम लागत बहुत कम है और अपने देश में गहन मशीनीकरण करती जा रही हैं। इन संघर्षरत लोगों में बेरोजगार नौजवान शामिल थे क्योंकि फ्रांस में 2000 और 2007 के बीच 7 सालों में 65% रोजगार हानि हुई थी और तब से बेरोजगारी बेलगाम बढ़ रही है। बीजों, श्रम लागत या कृषि उपकरणों की आकाश छूती कीमतों और उनके द्वारा उत्पादित फसलों के मामूली दाम मिलने से कर्ज जाल में फंसे किसान इस जुलूस में शामिल थे क्योंकि उनकी 'परोपकारी' सरकार अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों का मुकाबला करने के लिए कृषि उपजों की कीमतें कम रखती है और औसतन प्रतिदिन एक गरीब किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करने को मजबूर हो रहा है। राष्ट्रीय परीक्षाओं के सुधारों का प्रतिवाद कर रहे हाई स्कूल छात्रों ने अपनी राष्ट्रीय यूनियन के आह्वान पर सड़क अवरोध लगाकर और हड़ताल के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि पुलिस द्वारा उन्हें घेर लिए जाने और गिरफ्तार कर लिए जाने के बावजूद वे रुके नहीं। इस उफनते जन-सैलाब में शामिल थे मध्यम वर्गीय कार मालिकों सहित आम जन साधारण जो तेल की कीमतों में वृद्धि का विरोध कर रहे थे जिसके चलते तमाम आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ घर किराए, परिवहन लागत में बढ़ोतरी कार मालिकों के लिए नाकाबिले बरदाश्त थी। दरअसल आम आदमी की तो पहुंच से ही बाहर हो गई थी। इनमें शामिल था आबादी के हाशिए पर धकेल दिया गया तबका, बूढ़े और पेंशनभोगी जो पेंशन और अन्य सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में की गई कटौती का विरोध कर रहे थे जो उनके जिंदा रहने का एकमात्र संबल था। लाखों की संख्या में रेलियां निकाल रहे ये लोग और ऐसे ही दूसरे लोग मार्सेल्स, पैरिस और अन्य बड़े

पैरिस में हाल ही हुआ विशाल जन प्रतिवाद

(शेष पृष्ठ 7 पर)

(पृष्ठ 1 का शेष)

खुले अधिवेशन में कॉमरेड प्रभास घोष

गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं

में भारत 100वें नंबर पर था। अब वह फिसलकर 103वें नंबर पर चला गया है। यही है तरक्की! भारत में रोजाना 20 करोड़ 30 लाख लोग भूखे दिन बिताते हैं। हाल के वर्षों में भुखमरी के शिकार लोगों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। भूख से रोजाना 7 हजार लोगों की मौत होती है। भारत में पूरी दुनिया के एक तिहाई गरीबों का निवास है। अब तक 3 लाख 50 हजार किसानों ने खुदकुशी की है। रोजाना 10 हजार लोग बिना इलाज के मरते हैं। रोजाना 3 हजार बच्चे कुपोषण से मरते हैं। हमारे 123 करोड़ के देश में 70 करोड़ बेरोजगार हैं। कुछ दिनों पहले रेलवे में 90 हजार पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकला था। इसके लिए 2 करोड़ 80 लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन भरा था। कल्पना कीजिये, देश के लोग किस संकटपूर्ण स्थिति में जी रहे हैं! उत्तर प्रदेश में 362 चपरासी के पदों के लिए 23 लाख आवेदन भरे गये थे, जिनमें 255 लोग पीएचडी डिग्रीधारी थे। स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारियों की तादाद भी काफी थी। पश्चिम बंगाल में 5400 ग्रुप डी के पदों के लिए 18 लाख लोगों ने आवेदन भरा है। इसमें भी पीएचडी डिग्रीधारी हैं, डाक्टरेट हैं, इंजीनियर हैं। यह है देश की भयावह तस्वीर। लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है।

इन वर्षों में किनकी तरक्की हुई है?

क्या इन वर्षों में देश में तरक्की नहीं हुई है? तरक्की हुई है बड़े उद्योगपतियों की, बड़े व्यवसायिओं की। 2016 में भारत के एक प्रतिशत अमीर कुल सम्पदा के 51 प्रतिशत के मालिक थे। दो सालों के भीतर इन एक प्रतिशत अमीरों के पास देश की कुल सम्पदा का 73 प्रतिशत चला गया। आज भारत के 90 प्रतिशत लोगों की जो सम्पदा है, उसके बराबर 57 करोड़पतियों की सम्पदा हो गयी है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की संपत्ति 31 जुलाई 2018 की तारीख में 3 लाख 71 हजार करोड़ रुपये हो गयी है। बड़े उद्योगपति दिलीप सिंघवी का मुनाफा 1 लाख 28 हजार 122 करोड़ रुपये है। बड़े उद्योगपति गौतम अडाणी और अजीम प्रेमजी की कुल सम्पत्ति क्रमशः 1 लाख 70 हजार 230 करोड़ तथा 1 लाख 30 हजार 251 करोड़ रुपये है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की संपत्ति में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उनके बेटे जय शाह की कंपनी का मुनाफा एक साल में 5 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 80 हजार करोड़ रुपये हो गया, जो कि 16 हजार गुने की बढ़ोतरी है। यहां तक कि भगवाधारी बाबा रामदेव की संपत्ति में भी 117 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। ये सभी सैकड़ों करोड़ रुपयों के मालिक हैं।

इसके अलावा मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सम्पत्ति करोड़ों में है। जनता की सेवा के नाम पर वे दोनों हाथों से पैसे लूट रहे हैं। उद्योगपतियों, बड़े व्यवसायियों, मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं का भ्रष्टाचार सामान्य बात हो गयी है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो 'करप्शन हैज बिकम दि लॉ ऑफ दि लैंड'। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन ज्यादा चोरी कर रहा है, कौन कम चोरी कर रहा है। कौन पकड़ा गया है और कौन फरार है। सरकार दिवालिया हो चुकी है। इसलिए, बजट घाटा बढ़ रहा है। इस बढ़ते घाटे की भरपाई के लिए सरकार देशी-विदेशी स्रोतों से कर्ज ले रही है, जनता पर टैक्सों का बोझ लाद रही है और महंगाई बढ़ा रही है। खबर है कि 2014-15 और 2018-19 के बीच पेट्रोल और डीजल पर लगाये गये टैक्स से सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये कमाये हैं। अब सरकार रिजर्व बैंक में रखे जनता के पैसों को हड़पना चाहती है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से कहा जा रहा है कि वह अपने अतिरिक्त रिजर्व को सरकार को ट्रांसफर कर दे। पैसों की कमी का बहाना बनाकर केन्द्र सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती कर रही है। साथ ही वह इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उद्योगपतियों-व्यापारियों के हाथों सौंप रही है, ताकि इन्हें व्यवसायिक आधार पर चलाते हुए जनता को निचोड़ कर काफी मुनाफा कमाया जा सके। सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदाओं को रोकने का न कोई इंतजाम किया है और न ही इसने सिंचाई और पेयजल का कोई प्रबंध ही किया है। दूसरी ओर इसने एकाधिकार घरानों और बड़े कारपोरेट घरानों को बैंकों के 10 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के कर्ज हड़पने का मौका दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, इन एकाधिकार घरानों और कारपोरेट घरानों से सरकार को मिलने वाले 2 लाख 72 हजार करोड़ रुपये के टैक्स भी माफ कर दिये गये हैं। अब तक विदेशों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपये के काले धन को इकट्ठा करने का मौका भी दिया गया है। यह तस्वीर का दूसरा पहलू है।

दो भारत

इसलिए, दो भारत हैं–एक भारत बड़े उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों का है। उनकी करोड़ों की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक दूसरा भारत है करोड़ों मेहनतकशों का, जो बदहाल हैं, भूखे और बेरोजगार हैं। वे भूख से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और नवजात बच्चों को बेच रहे हैं। फैसला आपको करना है कि वोट आधारित राष्ट्रीय बुर्जुआ और क्षेत्रीय पार्टियां किसकी तरफ हैं–तेजी से बढ़ते हुए अमीरों की तरफ या कि बदहाली और गरीबी का दंश झेल रहे अनगिनत देशवासियों की तरफ।

इसके अलावा और भी खुलासे हुए हैं। आज के अखबार में खबर छपी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बहाने कि यह अपराधियों की जांच और अभियोग की कार्रवाई को बाधित करेगा सूचना आयोग को इस संबंध में ब्योरा देने से इंकार कर दिया है कि विदेशों से कितना कालाधन लाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहते हुए कि इस तरह की सूचना प्रदान करना 'व्यक्तिपरक और बोझिल' हो सकता है, इस बात का भी ब्योरा देने से इंकार कर दिया है कि किन-किन केन्द्रीय मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कौन-कौन से आरोप हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वैसे उद्योगपतियों के नामों की सूची जारी करने की आयोग की मांग को भी ठुकरा दिया है, जिन्होंने बैंकों द्वारा मुहैया कराये गये कर्ज की बड़ी राशि को हड़प लिया है। वजह साफ है। उस सूची में जनता द्वारा बैंकों में जमा किये गये करोड़ों रुपये हड़पकर विदेश भागने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों, बीजेपी नेताओं के मित्रों तथा अनेक बड़े नाम हैं। इसलिए, सरकार सूची को सार्वजनिक करना नहीं चाहती है। तब सरकार किसके हित में काम कर रही है? निश्चित तौर पर इसे आप समझ रहे हैं।

बढ़ती बेरोजगारी, बदहाली और गरीबी वाला भारत

आज देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। करोड़ों मजदूरों की छंटनी हो रही है। नये पदों का सृजन नहीं हो रहा है। कल-कारखाने बंद हो रहे हैं। शासक हलकों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि कल-कारखाने इसलिए बंद हो रहे हैं, क्योंकि बाजार नहीं है। जितने भी मजदूरों की बहाली हो रही है, वह स्थाई नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हो रही है। इनके काम का समय निश्चित नहीं है, वेतन निश्चित नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम –यह एक नयी चीज शुरू हुई है। कार्यस्थल पर कोई श्रम कानून नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। गांवों की ओर देखिये, गांव श्मशान बन गये हैं। गांवों में युवक-युवतियां नहीं हैं, क्योंकि वहां कोई रोजगार नहीं है, जीने का कोई साधन नहीं है। इसलिए वे इस शहर से उस शहर की ओर भाग रहे हैं। यहां तक कि वे विदेश भी जा रहे हैं। इनका नाम है माइग्रेंट लेबर (प्रवासी मजदूर)। उनके लिए कहीं भी स्थाई काम नहीं है। शायद आपको पता न हो कि नौकरी देने के नाम पर दलालों ने इस देश के तीन करोड़ युवाओं को विदेशों में बेच दिया है। वे हैं स्लेव लेबर, गुलाम मजदूर। उन्हें देश में लौटने तक नहीं दिया जा रहा है। उनसे रात-दिन काम कराया जाता है और उन्हें उतना ही खाने को दिया जाता है जितना खाकर वे जिन्दा रह सकें। किसी तरह की मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। यहां तक कि उन्हें बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है। सोचिए, किस तरह की असहनीय गरीबी ने देश के तीन करोड़ युवाओं को विदेशों में गुलामों के तौर पर काम करने को मजबूर कर दिया है। कुछ व्यापारी कभी नौकरी देने के नाम पर, तो कभी शादी के नाम पर हजारों लड़कियों को गांवों से बाहर ले जाते हैं और फिर वे उन बेबस लड़कियों को देश-विदेश के देह व्यापार के बाजार में बेच देते हैं। यह देह व्यापार दिन पर दिन तेजी से फैल रहा है। यह देश के 'विकास' की एक और भयावह तस्वीर है। जनतंत्र दिवस 26 जनवरी आने वाला है। उस दिन बड़े-बड़े समारोह होंगे। नेतागण अपने लम्बे-लम्बे भाषणों में बड़े-बड़े वायदे करेंगे। 5 या 7 सितारा होटलों में भव्य समारोह होंगे, सजावटें होंगी, आतिशबाजियां होंगी और वैभवपूर्ण रात्रिभोज होगा। जब कूड़ेदान में जूठन फेकें जायेंगे, तो फुटपाथ के बच्चे उस जूठन को लेकर छीना-झपटी करेंगे। वे भी इंसान के बच्चे हैं। लाखों बच्चे फुटपाथ पर ही जन्म लेते हैं और वे वहीं मर जाते हैं। कोई उनकी परवाह नहीं करता। वे बेसहारा बच्चे यह भी नहीं जानते हैं कि उनके मां-बाप कौन हैं। जब अंधेरा होता है, तो शहरों के स्टेशनों, बस पड़ावों, बाजारों और नुक्कड़ों पर हमारी माताएं और बहनें बड़ी तादाद में निकल पड़ती हैं अपना जिस्म बेचने। अपने भूखे बच्चे की रोटी या बीमार पति की दवा के लिए उनके पास और कोई उपाय नहीं होता है। इन वर्षों में इसी प्रकार का 'विकास' हुआ है अपने देश में! कांग्रेस ने लम्बे दिनों तक राज किया। अब बीजेपी सत्ता पर विराजमान है। इन दोनों पार्टियों ने यही 'विकास' दिया है देश की जनता को। इन्होंने बड़े उद्योगपतियों और बड़े व्यवसायियों के ही फलने-फुलने की गारंटी की है, जो उत्पीड़ित जनता के खून का अंतिम कतरा तक चूसकर अपने मुनाफे का पहाड़ खड़ा करते रहे हैं। किसकी तरक्की हुई है? क्या यह वही आजादी है, जिसके लिए शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने अपनी जान दी थी। क्या ऐसी ही आजादी हासिल करने के लिए हजारों युवक-युवतियों ने शहादत का सेहरा पहना था? क्या इसी आजादी को पाने के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने संघर्ष किया था।?

राजनीति में केवल दो ही ताकतें हैं

अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन के स्थान पर देश में दमनकारी पूंजीवादी शासन कायम हुआ है। यही बात हमारे आदरणीय नेता और शिक्षक कॉ. शिवदास घोष ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जनता को आजादी नहीं मिली है। मुट्ठीभर पूंजीपतियों को लूटने और अपनी मर्जी से शोषण करने की आजादी मिली है। उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज वर्ग विभाजित है। एक ओर शासक पूंजीपति वर्ग है, जिसका केवल एक ही मकसद है अधिक से अधिक शोषण के जरिये अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। दूसरी ओर विशाल तादाद में गरीब जनता है, दमित-उत्पीड़ित मजदूर, किसान और मध्यमवर्ग है। उन्होंने आगे कहा था कि राजनीति में सतही तौर पर कई विरोधी ताकतें दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में राजनीति में केवल दो ही विरोधी ताकतें हैं। एक वह है, जो बड़े उद्योगपतियों व्यवसायियों की वफादारी के साथ सेवा करती है, प्रचंड लूट और शोषण को बढ़ावा देती है तथा अत्याचारियों और लूटेरों की रक्षा करती है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तथा तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इसी राजनीति का अभ्यास करती हैं। दूसरी वह है, जो निर्मम पूंजीवादी दमन के खिलाफ जन संघर्षों के निर्माण की राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है। उच्च विचारधारा, संस्कृति और नीति-नैतिकता पर आधारित यह राजनीति पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत की सरजमीन पर सही क्रांतिकारी पार्टी एसयूसीआई (सी) इस राजनीति की मशाल वाहक है। इसी लक्ष्य के साथ हम अपना संघर्ष चला रहे हैं।

पूंजीवाद तार्किकता को नष्ट कर रहा, अंधता फैला रहा

आज जीवन के हर क्षेत्र में पूंजीवादी हमले हो रहे हैं। शिक्षा के अवसर, ज्ञान के अवसर में लगातार कटौती हो रही है। शैक्षिक पाठ्यक्रमों को धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मवाद के अनुरूप मोड़ा जा रहा है। जबकि नवजागरण के पुरोधा राममोहन राय और विद्यासागर ने कहा था कि वेद-वेदांत की शिक्षा नहीं, संस्कृत भाषा की शिक्षा नहीं, बल्कि शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विज्ञान, तर्कशास्त्र तथा वैज्ञानिक दर्शन शामिल होने चाहिए। नये इंसान के निर्माण के लिए इस तरह की धर्मनिरपेक्ष और जनवादी शिक्षा लागू होनी चाहिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और जनवादी शिक्षा संबंधी उनकी समझ और उनके दृष्टिकोण के खिलाफ कांग्रेस ने पहला हमला किया। वैज्ञानिक मानसिकता को खत्म करने, तार्किक नजरिये को नष्ट करने और बहसों पर रोक लगाने के जरिये बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गयी है, ताकि कोई आपत्ति न उठा सके, कोई सवाल न उठा सके, कोई किसी बहस में न जा सके, बल्कि जो नेता कहें उसे अंधे की तरह मानता चले। इसके लिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा लागू की है ताकि लोगों के दिमाग में अंधविश्वास भरा जा सके। वे धार्मिक उन्माद भी पनपा रहे हैं।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद झगड़े पर

राम को लेकर रस्साकशी चल रही है। कौन राम का सही उत्तराधिकारी है, इसे लेकर दावे और प्रतिदावे हो रहे हैं। राम एक पौराणिक चरित्र हैं, ऐतिहासिक चरित्र नहीं। इतिहास में आपको कहीं राम नहीं मिलेंगे। इतिहास में आपको गौतम बुद्ध मिलेंगे, महावीर मिलेंगे, शंकराचार्य मिलेंगे।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

(पृष्ठ 2 का शेष)

खुले अधिवेशन में कॉमरेड प्रभास घोष

दो तरह के भारतीय हैं – एक हैं मुट्ठी भर शोषक-उत्पीड़क शासक पूंजीपति और दूसरे हैं शोषित-पीड़ित बहुसंख्यक मेहनतकश लोग

राम एक काल्पनिक चरित्र है। चारों वेदों, सभी छह उपनिषदों, गीता, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत –कहीं भी राम का जिक्र नहीं है। अब, चुनाव को ध्यान में रखकर राम को लेकर प्रचार चल रहा है। क्या इन स्वघोषित राम के चेलों को सही हिन्दू कहा जा सकता है? कहा जाता है कि राम के जन्म से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और आगे क्या होगा, इसकी भी भविष्यवाणी की। लेकिन कहीं भी उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी नहीं की कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनायी जायेगी। तुलसीदास ने जब रामचरित मानस की रचना की, उस दौरान बाबरी मस्जिद थी। क्या तुलसीदास ने कहीं लिखा है कि राम के जन्मस्थान पर बाबरी मस्जिद बनायी गयी है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। श्री चैतन्य देव, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द – हिन्दुओं ने जिन्हें अवतार माना है, उन्होंने भी बाबरी मस्जिद देखी थी। लेकिन उनमें से किन्हीं ने भी कभी नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद राम के जन्मस्थान पर बनी हुई है। तब क्या हम मान लें वे सभी कायर थे? कांग्रेस ने ही सबसे पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की शुरुआत की। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और वहां रामलला की पूजा शुरू करवायी। मकसद साफ था धार्मिक भावना को उकसाकर हिन्दू वोट तैयार करना। बीजेपी ने जब देखा कि कांग्रेस राम का इस्तेमाल हिन्दू वोट बटोरने में कर रही है, तो उसे इसमें बड़ा खतरा महसूस हुआ। बीजेपी ने तत्काल रथयात्रा निकाल दी, देशभर में खूनी दंगे करवाये, बाबरी मस्जिद तोड़ने का आह्वान किया और इस प्रकार धार्मिक लाइन पर कृत्रिम ध्रुवीकरण करते हुए अपनी चुनावी उम्मीदों को साकार किया। इसके बाद 1992 में तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री की निष्क्रियता पर आरएसएस-संघ परिवार के उन्मादी सैनिकों ने अपने अगुआ नेताओं की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद जैसी एक ऐतिहासिक इमारत को जमींनदोज कर दिया। इस बार भी, चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्माद पैदा करने का एक घिनौना खेल शुरू हुआ है।

क्या आरएसएस-बीजेपी हिन्दुत्व के सही अनुयायी हैं?

हम मार्क्सवादी नास्तिक होते हैं। लेकिन मैं एक प्रासंगिक सवाल उठाना चाहता हूं। क्या आरएसएस-बीजेपी सचमुच हिन्दुत्व को मानते हैं? विवेकानन्द ने कहा था– पहले भूखे को रोटी दो, उसके बाद धर्म की बात करना।[1] उन्होंने स्वघोषित हिन्दुओं से पूछा कि वे भूखे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं।[2] उन्होंने कहा था कि अगर उनका कोई बेटा होता, तो वह बौद्ध बन सकता था, उनकी पत्नी ईसाई बन सकती थीं और वे खुद मुसलमान बन सकते थे। इसमें नुकसान कहां है?[3] वे बाइबिल, कुरान और वेद के समन्वय से एक धर्म बनाना चाहते थे।[4] उन्होंने यह भी कहा था कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को चोट नहीं पहुंचाएगा।[5] विवेकानन्द के गुरु रामकृष्ण ने मस्जिद में महीनों नमाज पढ़ी थी, चर्च में प्रार्थना की थी और साथ ही काली की पूजा भी की थी। क्या वे हिन्दुत्व के प्रतिनिधि थे या आज के आरएसएस-बीजेपी के नेता हिन्दुत्व के अनुयायी हैं? आरएसएस-बीजेपी से पूछिए कि क्यों वे हिन्दुत्व के नाम पर यह उन्माद फैला रहे हैं।? क्या यह संकीर्ण साम्प्रदायिक स्वार्थ में चुनावी फसल काटने का साधन नहीं है? जब भी चुनाव आता है, तब राम मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है और साम्प्रदायिक जहर फैलाया जाता है। यह खतरनाक रूप से बढ़ रहा है।

आरएसएस-बीजेपी के हिन्दुत्व के नारों के पीछे का मंसूबा

हिन्दुत्व के विचार फैलाने के पीछे आरएसएस-बीजेपी के दो मकसद काम कर रहे हैं। पहला है, हिन्दू वोटों को एकत्रित करते हुए अपनी चुनावी संभावनाओं को साकार करना। अभी मोदी और राहुल गांधी में होड़ मची है कि कौन पहले किस मंदिर में घुसेंगे। यह साबित करने की भी प्रतियोगिता चल रही है कि कौन बड़ा हिन्दू है। दूसरा मकसद है जनता का एका तोड़ना। गरीब मजदूरों, किसानों और मध्यमवर्ग में एक-दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दो। मैं हिन्दू हूं, तुम मुसलमान हो। मैं अगड़ी जाति का हूं, तुम पिछड़ी जाति के हो। तुम दलित हो, वह आदिवासी है आदि आदि। इस प्रकार मेहनतकश जनता के विभिन्न तबकों के बीच एक विभाजन तैयार किया जा रहा है, ताकि वे एकताबद्ध होकर खड़ा न हो सकें और शासक पूंजीपति वर्ग और उसके सेवकों बुर्जुआ सरकारों के खिलाफ संघर्ष न कर सकें। यही वजह है कि सुनियोजित ढंग से साम्प्रदायिक, जातीय और नस्लीय उन्माद की आग और हिंसा भड़कायी जा रही है।

दूसरा मकसद है लोगों में अंध धार्मिक विश्वास पैदा करना। आरएसएस-बीजेपी जैसी साम्प्रदायिक- कट्टरपंथी ताकतें आम लोगों को यह बताते हुए शैतानी खेल खेल रही हैं कि 'तुम गरीब क्यों हो, तुम बेरोजगार क्यों हो', क्योंकि तुम्हारा नसीब खराब है। तुम पूर्वजन्म में किये गये अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हो। अम्बानी और अदाणी जैसे एकाधिकार पूंजीपति, जो हजारों-हजार करोड़ रुपये लूट रहे हैं और निर्ममतापूर्वक लोगों का शोषण कर रहे हैं, उन्होंने पूर्वजन्म में इतना पुण्य कमाया है कि भगवान ने उन्हें गरीबों का खून चूसने के लिए भेजा है। और गरीबों और बेसहारों, तुम खुशी-खुशी भूखे मर जाओ, इलाज के अभाव में मर जाओ। अगर तुम बिना विरोध किये आनन्दपूर्वक मरोगे, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी और अगले जन्म में आराम मिलेगा। इसलिए कभी कोई सवाल मत करो, बहस मत करो। तुम्हारे साथ हो रहे दमन-उत्पीड़न का कारण मत ढूंढो। क्योंकि यह सब भगवान द्वारा तय किया हुआ है। भगवान की इच्छा ही कर्म है। सबकुछ खुदा की मर्जी है, नसीब का खेल है। इसलिए अपने सारे दु:ख-कष्टों और गरीबी के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ, बल्कि खुद के पूर्वजन्म के पाप और नसीब को दोषी ठहराओ। इस तरह की चालाकी और साजिश चल रही है। इन सबके बारे में जनता को सचेत रहना होगा।

युवाओं की नैतिक रीढ़ तोड़ने के लिए अश्लीलता और भद्देपन को अंधाधुंध बढ़ावा

एक और भयंकर साजिश चल रही है। जब देश में साम्राज्यवादी अंग्रेज शासक थे, तो वे चाहते थे कि इस देश के छात्र-युवा उजरती गुलाम बनें। लेकिन वह संभव न हो सका। इस देश के अनगिनत छात्र-युवाओं ने आनन्दपूर्वक अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किसी भी लौकिक लाभ या तथाकथित पारिवारिक जीवन की सुख-सुविधा की परवाह नहीं की और आजादी आंदोलन में शामिल होने के लिए नौकरी ठुकरा दी। वे जेल गये, साम्राज्यवादी शासन की लाठियों और गोलियों का सामना किया और अपनी शहादत दी। वह सही यौवन का प्रतीक था। आज शासक पूंजीपति वर्ग और उसके रक्षक यौवन के सारतत्व को नष्ट कर रहे हैं। वे छोटे लड़कों को 'खाओ, पीओ, मौज करो' की संस्कृति अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे उन्हें जुआ के अड्डों पर जाने, नशाखोरी करने और महिलाओं की देह को लेकर भद्दी चर्चाओं में मशगूल रहने की लत पकड़ा रहे हैं। ब्लू फिल्मों के लगातार प्रोत्साहन और कामुक वस्तुओं के जरिये साइबर नेटवर्क सहित विभिन्न मीडिया द्वारा वे अश्लीलता और यौन विकृतियों को फैला रहे हैं। सोचिए, छह माह की बच्ची, दो साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ है। जरा एक बार सोचिए, स्थिति कितनी बदतर हो गयी है। छह साल की बच्ची से लेकर सौ साल की बूढ़ी महिला को भी निर्ममतापूर्वक बलात्कार करने से बख्शा नहीं जा रहा है। पिता के खिलाफ बेटी बलात्कार का आरोप लगा रही है। शिक्षक के खिलाफ छात्रा बलात्कार और छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं। कितनी भयावह स्थिति है! यहां तक कि सम्पत्ति हथियाने के लिए वृद्ध मां-बाप को उनके बच्चे घर से भगा दे रहे हैं या उनकी हत्या कर दे रहे हैं। परिवार में भी प्यार नहीं है, स्नेह नहीं, कोमल भावनाएं नहीं हैं, मूल्य नहीं हैं। हम ऐसे ही देश में रह रहे हैं! यही तो है वह 'तरक्की' जिसकी शासक वर्ग और उसके चाटुकार शेखी बघारते हैं। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पशु जगत में भी नहीं होते हैं। पूंजीपति वर्ग देश के युवाओं को अवनति के गर्त में धकेल रहा है ताकि उनके अंदर इंसानियत, विवेक, तमाम मानवीय गुण खत्म हो जायें और वे अमानुष बन जायें। यदि युवा गिरावट और अध:पतन के शिकार हो जायेंगे, यदि उनकी नैतिक रीढ़ टूट जायेगी, तो वे आसानी से खरीदे जा सकेंगे और पैसे देकर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल किये जा सकेंगे। अब, अगला लोकसभा चुनाव आने वाला है। बेरोजगार और सांस्कृतिक तौर पर प्रदूषित वे युवा पैसे, शराब, नशा और मौज-मस्ती के लिए कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी बुर्जुआ पार्टी के वॉलंटियर के रूप में भर्ती हो जायेंगे। वे समाज में हो रहे किसी भी गलत काम या अन्याय का न कभी विरोध करेंगे और न ही कभी संघर्ष में शामिल होंगे। इस मकसद को पूरा करने के लिए शासक वर्ग इस बात की गारंटी करना चाहता है कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस, खुदीराम, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, अशफाकउल्ला खान के जीवन और विचारों को लेकर कोई चर्चा न हो। देश के बहुत सारे लोग, खासकर युवा राममोहन, विद्यासागर, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, शरत्चन्द्र, प्रेमचंद, ज्योतिबा फुले, सुब्रमनियम भारती, ज्योति प्रसाद, गोपबंधु दास और देश के अन्य महापुरुषों को याद नहीं करते। शासक वर्ग की यह भरपूर कोशिश रही है कि लोग इन महापुरुषों को भूल जायें ताकि वे मानवीय गुणों से वंचित हो जायें और अमानुष बन जायें। तब शासक बुर्जुआ वर्ग के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। यही है पूंजीवादी दमन की प्रकृति, उसका तेज हमला और उसकी साजिशें। इस संबंध में हमारी पार्टी लोगों को जागरूक करना चाहती है और इस दुष्कर पूंजीवादी शोषण तथा उसकी साजिशों से उन्हें सावधान करते हुए सही यौवन को जगाना चाहती है।

जरा सोचिए, यदि आज विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले, सुभाषचन्द्र बोस, विवेकानन्द, भगत सिंह, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय या सुब्रमनियम भारती जीवित होते और देश की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते, तो वे देशवासियों से क्या कहते? क्या वे कांग्रेस-बीजेपी की गुलामी करने को कहते? क्या वे मस्जिद ढाहकर मंदिर बनाने को कहते? क्या वे शराब पीने, नशाखोरी करने की सलाह देते? क्या वे महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करने को कहते? या कि वे इन तमाम खतरों और सड़न के खिलाफ लड़ने का आह्वान करते, मानवीय गुणों के आधार पर दृढ़ता के साथ खड़े होकर गलत और अन्याय के खिलाफ लाठी उठाने को कहते। केवल हमारी पार्टी महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचारधारा के आधार पर पुराने जमाने के महापुरुषों के विचार और शहीदों के गौरवपूर्ण जीवन और योगदान की चर्चा कर रही है, जिन्हें शासक पूंजीपति वर्ग विस्मृति के गर्भ में धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमारी पार्टी यौवन को, मानवीय गुणों को हासिल करने के चर्चा-अभ्यास को तथा उच्च संस्कृति व नीति-नैतिकता को जगाना चाहती है।

छद्म मार्क्सवादियों का अवसरवाद और विश्वासघात

हम भी चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन वामपंथ और क्रांतिकारी विचार को त्यागकर नहीं। हम सीपीआई, सीपीआई (एम) की तरह कांग्रेस को 'सेक्युलर' तमगा नहीं लगाते। 'सेक्युलरिज्म' शब्द का एक निश्चित मतलब है। दार्शनिक तौर पर सेक्युलरिज्म का मतलब है किसी भी अति-प्राकृत सत्ता की अस्वीकृति और एकमात्र वास्तविकता के तौर पर भौतिक जगत की स्वीकृति है। राजनैतिक तौर पर सेक्युलरिज्म का मतलब सुभाषचन्द्र बोस के शब्दों में कहा जाये तो राजनीति के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं रहेगा। राजनीति का संचालन राजनैतिक-आर्थिक-वैज्ञानिक तर्क द्वारा होगा। भगत सिंह ने इस सेक्युलरिज्म का समर्थन किया था। रवीन्द्रनाथ-प्रेमचंद-शरतचन्द्र ने इस सेक्युलरिज्म की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही धर्म आधारित राष्ट्रवाद का प्रचार करती आ रही है। गांधीजी ने भी भारत के बुर्जुआ वर्ग के हित में इसकी वकालत की थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चर्चा नहीं चाहते थे। यही धर्म आधारित राष्ट्रवाद अंतत: हिन्दू धर्म आधारित राष्ट्रवाद में तब्दील हुआ। इसके बाद, अंग्रेज साम्राज्यवादी शासकों ने मुस्लिम समुदाय को आजादी आंदोलन से अलग-थलग रखने का षडयंत्र रचा, हिन्दू-मुस्लिम विभाजन पैदा किया और अंतत: पाकिस्तान का निर्माण किया। नहीं तो, देश के बंटवारे जैसी बर्बादी नहीं होती। इसलिए कांग्रेस कभी भी सेक्युलर नहीं थी, आज भी नहीं है। चुनाव के मैदान में चूंकि वह बीजेपी के विरोध में खड़ी है, इसलिए वह सेक्युलर है -यह झूठ है, लोगों को भ्रमित करना है। सीपीआई (एम) और सीपीआई कांग्रेस की

(शेष पृष्ठ 4 पर)

(पृष्ठ 3 का शेष)

खुले अधिवेशन में कॉमरेड प्रभास घोष

चुनावों में बीजेपी का विरोध करने से ही कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाती

पूंछ पकड़कर चल रही हैं–सिर्फ चुनावी हित में, कुछ सीट पाने के लिए। हम ऐसी राजनीति का अभ्यास नहीं करते हैं। वह कांग्रेस ही थी, जिसने आपातकाल लगाया था, नागरिक और जनवादी अधिकारों का हनन किया था, विरोध की आवाज को दबाया था, प्रेस की आजादी में कटौती की थी और टाडा–मीसा–एसमा जैसे काले कानून लागू किये थे। जिस तरह बीजेपी ने लगातार दंगा फैलाया है, नरसंहार करवाया है और जिसके चलते भातृघाती खून–खराबा हुआ है, उसी तरह कांग्रेस ने भी राउरकेला (ओड़िशा), भागलपुर (बिहार), नेल्ली (असम) तथा दिल्ली में साम्प्रदायिक आग भड़कायी थी। इसी कांग्रेस को आज सीपीआई (एम) और सीपीआई द्वारा 'धर्मनिरपेक्ष' और 'जनवादी' कहा जा रहा है। हम वोट के लिए इस तरह के साफ झूठ का सहारा कदापि नहीं लेते। हमने हमेशा ही कहा है कि सीपीआई व सीपीआई (एम) मार्क्सवाद की बात तो करती हैं, लेकिन वे मार्क्सवादी नहीं हैं। उनके अतीत का इतिहास ऐसा नहीं कहता है। आजादी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग ने गांधीजी को सामने रख कर समझौता के जरिये सत्ता पर कब्जा जमाने की कोशिश की। उसी वजह से कांग्रेस ने कभी भी धर्मनिरपेक्ष–वैज्ञानिक सोच को सामने आने नहीं दिया और क्रांतिकारी संघर्ष का विरोध किया। इसके बजाय उसने धार्मिक सोच को बढ़ावा दिया। अहिंसा की नीति के अनुसरण के नाम पर इसने क्रांतिकारी आंदोलन के उभार को रोकना चाहा। इस बात का जिक्र करना प्रासंगिक होगा कि आजादी आंदोलन के अंदर एक गैर–समझौतावादी क्रांतिकारी धारा थी, जिसका प्रतिनिधित्व नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, भगत सिंह, सूर्य सेन, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे ही अन्य क्रांतिकारियों ने किया था। इस धारा के नायक सशस्त्र संघर्ष में यकीन रखते थे। अंग्रेज साम्राज्यवादी शासक और भारतीय बुर्जुआ वर्ग–दोनों इस क्रांतिकारी धारा से भयभीत थे। इसलिए उन्होंने सुभाषचन्द्र बोस के खिलाफ साजिश रची और उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया और निलम्बन के बाद वस्तुतः उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया। बहुतों को इस इतिहास की जानकारी नहीं है। आज सभी सुभाषचन्द्र बोस के भक्त बने हुए हैं। बीजेपी भी सुभाषचन्द्र बोस को याद कर रही है। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस–बीजेपी के सिद्धांतकार एम. एस. गोलवलकर ने आजादी आंदोलन के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो लोग अंग्रेजों का विरोध और भौगोलिक राष्ट्रवाद के आधार पर आजादी की बात करते हैं, वे प्रतिक्रियावादी हैं।[6] यदि इस सिद्धांत का समर्थन किया जाये, तो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस से लेकर देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, गांधी और नेहरू तक–सभी को देशभक्त नहीं, बल्कि प्रतिक्रियावादी मानना पड़ेगा। ऐसे थे गोलवलकर के विचार। उन्होंने हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू भारत की बात कही थी। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि गोलवलकर के इस कथन को हमने उस किताब से हटा दिया है। आरएसएस प्रमुख ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल अब उन्हें ऐसे सिद्धांत से दिक्कत हो रही है। लेकिन हटा देने से क्या होगा? आजादी आंदोलन के दौरान यही था आरएसएस का रूख। इतिहास को कैसे मिटाया जा सकता है? क्या आरएसएस कभी आजादी आंदोलन में था? कभी नहीं। आजादी आंदोलन का विरोध करने के अलावा आरएसएस की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। आरएसएस ने फासीवादी हिटलर की भी तारीफ की थी। यही उनका इतिहास है।

उस वक्त महान स्तालिन ने संयुक्त सीपीआई के नेताओं से कहा था कि वे बड़े राष्ट्रीय बुर्जुआ के प्रतिनिधि समझौतापरस्त सुधारवादियों की बजाय क्रांतिकारियों का समर्थन करें।[7] लेकिन तब संयुक्त सीपीआई, जिसमें सीपीआई (एम) के नेता भी शामिल थे, ने स्तालिन की सलाह नहीं मानी। बजाय इसके सीपीआई के नेताओं ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का विरोध किया और गांधीजी का समर्थन किया। यही उनका इतिहास है। सीपीआई और सीपीआई (एम) ने ऐसे बहुत–से कारनामे किये, जो सर्वथा मार्क्सवाद–विरोधी हैं। आज उसकी विस्तृत चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि संयुक्त सीपीआई ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। उसका मानना था कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज जापानी साम्राज्यवाद की पिट्ठू है। संयुक्त सीपीआई ने एक विचित्र सिद्धांत तैयार किया कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग राष्ट्रीयताएं हैं और इसी वजह से हिन्दू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग के साथ सीपीआई ने भी देश के बंटवारे का समर्थन किया।

वाम–जनवादी आंदोलन में सीपीआई (एम)–सीपीआई द्वारा भारी नुकसान

पश्चिम बंगाल कभी वाम–जनवादी आंदोलन का मुख्य केन्द्र हुआ करता था। संयुक्त बंगाल और बंटवारे के बाद पश्चिम बंगाल ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों की विरासत को आगे बढ़ाया। यहां कांग्रेस का प्रभाव लगभग न के बराबर था। अपने 34 सालों के लगातार शासन में सीपीआई (एम) ने शोषणकारी पूंजीवाद के हित साधने में इतना अत्याचार और दमन किया कि वही पश्चिम बंगाल आज सीपीआई (एम)–विरोधी मानसिकता की वजह से वामपंथ से नफरत कर रहा है। इस प्रकार सीपीआई (एम) ने वामपंथ और मार्क्सवाद को काफी नुकसान पहुंचाया है। यही उनकी घृणित भूमिका है। सीपीआई (एम)–सीपीआई बहुत पहले ही आंदोलन की राह छोड़ चुकी है। उनका एकमात्र लक्ष्य है चुनावी स्वार्थ पूरा करना। सिर्फ चुनावी फायदे के लिए सीपीआई (एम) ने 1977 में जनता पार्टी के साथ गठजोड़ किया था, जिस जनता पार्टी में आरएसएस भी था। सिर्फ वोट के लिए 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में अटल बिहारी वाजपेयी और ज्योति बोस ने कोलकाता में एक साथ सभा की। फिर आज वही सीपीआई (एम) चुनावी लाभ बटोरने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला रही है। हम वामपंथ के नाम पर ऐसी अवसरवादी राजनीति का अभ्यास नहीं करते। मैं सीपीआई और सीपीआई (एम) के वामपंथी मानसिकता से लैस ईमानदार कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील करता हूं कि वे इस पर विचार करें।

आज आर्थिक स्वार्थों को केन्द्र कर अपने बीच द्वन्द्व की वजह से भारत के बड़े पूंजीपतियों का खेमा आपस में बंटा हुआ है। संसदीय राजनीति में उनका एक तबका बीजेपी का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा कांग्रेस का। इसके अलावा, राष्ट्रीय पूंजी के साथ क्षेत्रीय पूंजी का द्वन्द्व तेज हो गया है। नतीजतन क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज ताकतवर हो गयी है। यदि सीपीआई (एम)–सीपीआई नेतृत्व को तनिक भी वर्ग–संघर्ष और जन आंदोलन की चिंता होती, तो वे बुर्जुआ खेमे के बंटवारे का लाभ उठा पाते। बजाय इसके वे कांग्रेस और अन्य बुर्जुआ पार्टियों के पीछे जा रहे हैं। वे उनके साथ किसानों की सभा में जा रहे हैं मानो कांग्रेस के शासन में किसानों ने खुदकुशी नहीं की, या कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर गोलियां नहीं चलायी। इनकी सहयोगी पार्टी भाकपा माले (लिबरेशन) ने भी अपनी पटना की जनसभा में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे को आमंत्रित किया और उसने भाषण भी दिया। इस तरह की मौकापरस्त राजनीति एमएलए या एमपी की 2–3 सीटें दिलवाने में भले मदद कर दे, लेकिन इससे पहले से ही कमजोर वामपंथी आंदोलन और भी कमजोर पड़ जायेगा। हमारी पार्टी इस तरह की अवसरवादी राजनीति का अभ्यास नहीं करती।

विश्व साम्राज्यवाद–पूंजीवाद का असमाधेय संकट

कामरेड्स और दोस्तो, विश्व साम्राज्यवाद–पूंजीवाद आज घोर असमाधेय संकट में फंसा हुआ है। उत्पीड़ित और बदहाल लोगों की खरीदने की ताकत नहीं है। इसलिए पूंजीवादी बाजार लगातार सिकुड़ रहा है। दुनिया भर में पूंजीवाद के इंजन के नाम से मशहूर अमेरिका आज प्रशांत महासागर में डूब रहा है। वही एक समय भूमंडलीकरण का पक्षधर था। जबकि वह आज कह रहा है कि भूमंडलीकरण नहीं चाहिए। बजाय इसके अब अमेरिकी शासक कह रहे हैं कि 'अमेरिका फर्स्ट', मतलब उसका हित पहले देखना होगा क्योंकि आज अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट है। अमेरिकी युवाओं के लिए काम नहीं है। कुछ दिनों पहले ही 'ओक्यूपाई वॉल स्ट्रीट' आंदोलन हुआ था। उसे आज साम्राज्यवादी चीन टक्कर दे रहा है, जहां समाजवाद खत्म होकर पूंजीवाद स्थापित हुआ है। उसके साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है साम्राज्यवादी रूस, साम्राज्यवादी जापान और एकीकृत यूरोप। नतीजतन अमेरिका, चीन, जापान, रूस, यूरोप–सभी घोर संकट में हैं। यह संकट पूरी पूंजीवादी व्यवस्था में है। सभी एक–दूसरे के बाजार को हड़पना चाहते हैं।

हालांकि इनमें से सभी दूसरे के बाजार में घुसना चाहते हैं, लेकिन वे अपने बाजार में घुसने नहीं देना चाहते। बाजार को लेकर बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो गयी है। सभी अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। साम्राज्यवादी ताकतों के बीच बाजार पर कब्जा करने के द्वन्द्व को लेकर ही पहला और दूसरा विश्वयुद्ध हुआ था। आज यह चिंता का विषय है कि साम्राज्यवादी ताकतों के बीच चल रहा ट्रेड वार इस बार कहां रुकेगा। एक और विषय गौरतलब है। औद्योगिक क्रांति के जमाने में पूंजीवाद राष्ट्र हित का नारा लगाकर राष्ट्रीय बाजार खड़ा करने के मकसद से आगे बढ़ा था। आगे चलकर एकाधिकार पूंजी और साम्राज्यवाद के स्तर में पहुंचकर उसी पूंजीवाद ने मल्टी नेशनल या बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को जन्म दिया। अब राष्ट्र हित की तिलांजली देकर बहुराष्ट्रीय संस्थान वैसे किसी भी देश में पूंजी निवेश करने को तैयार हैं, जहां वे सस्ते मजदूर और कच्चे माल के शोषण के जरिये अपना मुनाफा बढ़ाने में समर्थ हैं। इसके अलावा वे विदेशों में सस्ती लागत पर उत्पादित अपने सामानों को अपने देश के बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। नतीजतन अमेरिकी मल्टी नेशनल या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अपने अधिक से अधिक मुनाफे के हित और अमेरिकी पूंजीवाद के सामग्रिक हित के बीच द्वन्द्व नजर आ रहा है। अतएव अमेरिकी राष्ट्र भूमंडलीकरण के खिलाफ है जबकि अमेरिकी मल्टी नेशनल भूमंडलीकरण के पक्ष में। दूसरे साम्राज्यवादी–पूंजीवादी देशों की भी यही स्थिति है। भारतीय साम्राज्यवादी राष्ट्र के मल्टी नेशनल और कॉरपोरेट सेक्टर भी देश में पूंजी निवेश न कर विदेशों में पूंजी निवेश कर रहे हैं। पूंजीवाद आज जनता, देश, राष्ट्र –किसी की भी परवाह नहीं करता। जहां अधिक मुनाफा मिलेगा, वह वहीं जायेगा। फिर जरूरत पड़ने पर वह अपने हित में राष्ट्र का भी इस्तेमाल करता है। सम्पूर्ण पूंजीवादी–साम्राज्यवादी दुनिया घोर मंदी के दौर से गुजर रही है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। जब तक पूंजीवाद सत्ता में है, तब तक इस बढ़ती मंदी के हाथों से छुटकारा मिलना संभव नहीं है। क्योंकि, पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था अपने नियम से ही धीरे–धीरे बाजार को संकुचित और खत्म कर देती है। यह पूंजीवाद में अवश्यंभावी है। नतीजतन बेरोजगारी और छंटनी करोड़ों लोगों को तबाह कर रही है। लोग कंगाल, बदहाल और बर्बाद हो रहे हैं। उनमें खरीदने की क्षमता नहीं है? नतीजतन मंदी बढ़ेगी ही, क्योंकि पूंजीवाद को चाहिए अधिकतम मुनाफा। इसके लिए वे मजदूर वर्ग पर प्रचंड जुल्म ढाह रहे हैं।

मुक्ति समाजवाद में ही है

इसका एकमात्र विकल्प है पूंजीवाद को उखाड़ फेंककर समाजवाद की स्थापना। 1917 की रूस की महान नवम्बर क्रांति ने रास्ता दिखाया है। सोवियत समाजवाद 70 सालों तक रहा। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, छंटनी नहीं थी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क थी। बहुत कम पैसे में किराये पर मकान मिल जाते थे। केवल मजदूर–किसान ही चुनाव में खड़े हो सकते थे। सोवियत संघ ने काफी कम समय में हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक तरक्की दर्ज की थी। इसने दिखा दिया कि मार्क्सवाद और समाजवाद जनता को क्या–क्या दे सकता है। इसलिए रोमां रोलां, बर्नार्ड शॉ, आइंसटीन, रवीन्द्रनाथ, शरतचंद्र, प्रेमचंद, सुब्रमनियम भारती, नजरूल, सुभाषचन्द्र बोस जैसे तमाम मार्गदर्शकों –सभी ने सोवियत समाजवाद की तारीफ की। वे सभी इस नयी सभ्यता के पक्ष में खड़े हुए थे। शहीद–ए–आजम भगत सिंह ने तो खुद को कम्युनिस्ट घोषित कर रखा था। यह समाजवाद अंदर से संशोधनवादियों की साजिशों और पराजित पूंजीपतियों के कुचक्रों की वजह से ढह गया। जिन्हें बाहर से साम्राज्यवादियों– पूंजीपतियों की ओर से भारी मदद मिली। इतिहास से हम जानते हैं कि दास–मालिक समाज के दौरान ही धर्म का आगमन हुआ। उस समय उत्पीड़ित गुलामों के हित में धर्म की एक प्रगतिशील भूमिका थी। हर धर्म यह दावा करता था कि वह ईश्वर की शक्ति से लैस है। अब तक हिन्दुत्व, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम –तमाम धार्मिक आंदोलनों को शुरुआती दौर में पराजय का सामना करना पड़ा, फिर जीत हुई, फिर पराजय हुई और अंततः जीत हुई। यदि हम नवजागरण से लेकर संसदीय व्यवस्था की स्थापना तक का हिसाब लें, तो बुर्जुआ जनवाद का इतिहास साढ़े तीन सौ सालों

(शेष पृष्ठ 5 पर)

(पृष्ठ 4 का शेष)

खुले अधिवेशन में कॉमरेड प्रभास घोष

सीपीआई(एम)-सीपीआई की गैर-वाम राजनीति व व्यवहार ने आरएसएस-बीजेपी के खतरे के जबरदस्त उभार में मदद की

का है। बुर्जुआ जनवाद को भी बार-बार विजय और पराजय के रास्ते से गुजरना पड़ा है। अब, समाजवाद के बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सोवियत समाजवाद को लड़ना पड़ा है दासप्रथा से लेकर सामंतवाद, पूंजीवाद तक हजारों वर्षों के वर्ग शोषण के खिलाफ। इस विशाल काम के परिप्रेक्ष्य में 70 वर्षों के समाजवाद का अस्तित्व काफी कम है। लेकिन हम निश्चित हैं कि केवल समाजवाद ही अभीष्ट मुक्ति ला सकता है।

फ्रांस की जिस बुर्जुआ जनवादी क्रांति ने एक समय 'समानता, स्वतंत्रता और भाइचारे' का परचम लहराया था, वह आज बुर्जुआ वर्ग द्वारा ही धूल धूसरित है, पद दलित है। संसदीय जनवाद आज संसदीय ठाट-बाट के आवरण में फासीवादी तानाशाही में तब्दील हो गया है। पूंजीवाद आज मानव सभ्यता का घोर दुश्मन बन चुका है। इसलिए पूंजीपति-मजदूर के संबंध को टिकाये रखकर, पूंजीवादी राजसत्ता को टिकाये रखकर तथा मुनाफे की लूट और मजदूरों के शोषण को जारी रखकर चुनाव के माध्यम से सरकार बदलकर जनता की असह्य पीड़ा का कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति की जरूरत है।

आज बुर्जुआ चुनाव एक बड़ा छलावा है

क्या चुनावी नतीजे जनता के जनादेश को प्रतिबिम्बित करते हैं? क्या यह 'जनता के द्वारा, जनता के लिए तथा जनता की' है? चुनावों में करोड़ों रुपयों का खेल होता है। इतनी बड़ी राशि देता कौन है? इसका जवाब है कि और कोई नहीं बल्कि पूंजीपति और बड़े व्यवसायी ही देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस उनके सेवक हैं। सत्ता में आकर ये पार्टियां शासक पूंजीपति वर्ग की सेवक की तरह काम करती हैं, वफादारी के साथ उनके आदेशों का पालन करती हैं। अब ये दोनों पार्टियां काफी पैसे खर्च कर रही हैं। वे मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉल, साईकिल और अन्य वस्तुएं मुफ्त में बांट रही हैं। अगर जनता कहे कि आसमान से चांद ला दिजीये, तो वे वोट के लिए वह भी लाने को तैयार हो जायेंगे। बेबस गरीब लोग सोचते हैं कि चूंकि सामान्य स्थिति मे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वोट बटोरू पार्टियों से जो कुछ भी मिलता है, उसे ले लिया जाये। चाहे वह एक साईकिल हो, एक ट्यूबवेल हो या फिर एक साड़ी या कमीज ही क्यों न हो– वे इसे उपहार के रूप में देखते हैं। लेकिन वास्तव में यह रिश्वत नहीं तो क्या है? मुफ्त की इन चीजों के लिए पैसे कौन दे रहा है? यह शासक पूंजीपति वर्ग है, जो फंड उपलब्ध करा रहा है। वे अपनी थोड़ी-सी राशि दे रहे हैं, ताकि आपके शोषण के जरिये आवश्यक सामग्रियों की कीमतें बढ़ाकर उसका कई सौ गुना उन्हें वापस मिल सके। यही उनका उद्देश्य है। आज चुनाव एक स्वांग के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। यह जनता के लिए एक बड़ा छलावा बन चुका है। इस स्वांग का पर्दाफाश करने तथा जनता को इस तथ्य से अवगत कराने के लिए कि चुनाव के जरिये किसी भी मौलिक समस्या का समाधान संभव नहीं है, हम चुनाव में भाग लेते हैं। हमें अपनी स्पष्ट क्रांतिकारी लाइन के आधार पर चुनावों में तब तक भाग लेते रहना होगा, जब तक कि जनता क्रांति के लिए तैयार नहीं हो जाती। यही है महान लेनिन की सीख। एक क्रांतिकारी पार्टी के तौर पर हम जिस तरह अपनी ताकत से जनता को संगठित कर उसके जीवन की ज्वलंत समस्याओं पर वर्ग संघर्ष और जन आन्दोलन गठित करते हैं, उसी प्रकार हम उसके अंग के तौर पर चुनाव भी लड़ेंगे। हम चुनाव के अवसरवादी स्वार्थ में सीपीआई (एम) और सीपीआई की तरह बुर्जुआ पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों तथा जातिवादी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर जनता को बेवकूफ नहीं बनायेंगे। हम नीति और वैचारिक आधार पर वर्ग संघर्ष एवं जन आंदोलन के हित में वाम व जनवादी पार्टियों की ताकतवर एकता चाहते हैं।

जनता को निश्चित तौर पर राजनीति समझनी होगी, दुश्मन और मित्र में फर्क पहचानना होगा।

कॉमरेड्स एवं मित्रो, मैं आपसे ईमानदारीपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। आजादी आंदोलन के दौरान गरीब और मध्यम वर्ग की सन्तानों ने प्राण दिये हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज हुआ है शोषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग। यह सर्वनाश कैसे हुआ? इसका मुख्य कारण यह रहा कि जनता ने राजनीति समझना नहीं चाहा। समझौतापरस्त नेतृत्व भी यही चाहता था कि लोग अंधे ही रहें, अनजान ही रहें। लोगों ने सोचा कि चूंकि वे ढेर सारी पेचीदगियों को, राजनीति के उतार-चढ़ावों को समझने में असमर्थ हैं, इसलिए नेता लोग ही सब कुछ तय कर दें। समझौतापरस्त नेतृत्व ने इसका फायदा उठाया। उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आया कि गांधीजी और सुभाषचन्द्र बोस में फर्क कहां है। वे समझ नहीं पाये कि नेताजी को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया गया, कांग्रेस से उन्हें क्यों बहिष्कृत किया गया। आज भी अगर लोग अंधे ही रह जायें, अनजान ही रह जायें और अखबार क्या कह रहे हैं, टीवी क्या कह रहे हैं, कौन कितना पैसा देगा, इसके आधार पर इसे वोट देंगे, उसे वोट देंगे, यदि ऐसा सोचें -तब वे बार-बार ठगी के शिकार होंगे। कहावत है कि 'जो लंका जाता है, वही रावण बन जाता है।' यह कहावत सही नहीं है। रामायण की कहानी के अनुसार राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान –सभी लंका गये थे। लेकिन कोई रावण नहीं बना। बल्कि रामायण की यही सीख है कि सीता का अपहरण नहीं होता, यदि वह रावण को पहचान पाती। रावण संन्यासी के भेष में आया था। सीता ने लक्ष्मण की बात की परवाह न कर लक्ष्मण रेखा पार की थी। आज भी चुनाव के दौरान ये सारे नेता हवाई जहाज से, हेलिकॉप्टर से आ रहे हैं। वे गांवों में, शहरों में घूम रहे हैं और बार-बार जनता से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं -हमें एक बार मौका दीजिए, हम आपके सेवक हैं। वे सभी पैसे वालों के समर्थन से चल रहे हैं। जब वे एक बार सत्ता में आ जायेंगे, तो उनका असली चेहरा उजागर हो जायेगा। आप उनके झूठे वायदों और छलावापूर्ण बातों से प्रभावित मत होइए।

आम जनता को अवश्य राजनीति समझनी होगी। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है–उन्हें इसकी पहचान करनी होगी। उन्हें निश्चित तौर पर आवश्यक चेतना और दृष्टिकोण विकसित करना होगा कि कौन-सी पार्टी शोषक वर्ग के लिए काम कर रही है और कौन-सी पार्टी मेहनतकशों के हित को आगे बढ़ा रही है। लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी के दर्द और छंटनी की पीड़ा से छटपटा रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं। बच्चे अपने वृद्ध मां-बाप को घर से निकाल दे रहे हैं। वे उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। दहेज के लिए पत्नी की हत्या की जा रही है। हजारों बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। महिलाओं की तस्करी में इजाफा हो रहा है। क्या यह ऐसे ही बेरोकटोक चलता रहेगा? या कि इन तमाम दुख-कष्टों, परेशानियों, बीमारियों, अपराधों और धोखाधड़ियों का कोई हल निकलेगा? इसका एकमात्र हल पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति में ही है। हमारी पार्टी महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचारधारा के आधार पर क्रांति के परचम को लेकर आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं फिर आपसे आह्वान करूंगा कि आप राजनीति समझिए और सही क्रांतिकारी नेतृत्व के अंदर संगठित होइए। मीडिया के प्रचारों में बह मत जाइए। आपको मीडिया में आज की इस सभा की खबर ज्यादा नहीं मिलेगी। हम लाखों लोगों की विशाल सभा करते हैं, लेकिन एकाधिकार पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित मीडिया हमारी खबर नहीं छापता है। क्योंकि वे जानते हैं कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ही एकमात्र पार्टी है, जो पूंजीपति वर्ग की दुश्मन है। मीडिया के बिना किसी प्रचार के हमारी पार्टी बढ़ रही है। 25 राज्यों से संग्रामी प्रतिनिधि यहां आये हैं। हमारे पास कोई एमपी-एमएलए नहीं है, मीडिया का कोई प्रचार भी नहीं है। कॉमरेड शिवदास घोष के विचार के बल पर तमाम दिक्कतों-परेशानियों का मुकाबला करते हुए हमारे कॉमरेड काम कर रहे हैं, गांव-शहर में जनता को प्रेरित कर रहे हैं। इस पार्टी को आप ताकतवर बनाइये ताकि आने वाले दिनों में हम और भी ताकतवर आंदोलन खड़ा कर सकें, संघर्ष विकसित कर सकें।

आज हमें हजारों खुदीराम, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकउल्ला खान, प्रीतिलता तथा ऐसे ही उज्जवल चरित्रों की जरूरत है, जो पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति के परचम को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस मकसद को लेकर ही हम शोषित जनता, खास तौर पर छात्र-युवाओं को आज के सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी विचार मार्क्सवाद-लेनिनवाद शिवदास घोष की विचारधारा से प्रेरित कर रहे हैं। हम मजदूरों, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग की मांगों को लेकर वर्ग संघर्ष और जन आंदोलन विकसित कर रहे हैं। हम इस संघर्ष में अन्य वामपंथी दलों और उनके कार्यकर्ताओं को शामिल करने की भी भरसक कोशिश कर रहे हैं। इस पार्टी को आप ताकतवर बनाइये ताकि आने वाले दिनों में हम और भी ताकतवर आंदोलन खड़ा कर सकें, संघर्ष विकसित कर सकें। इस अविराम संघर्ष को चलाते हुए हम चुनाव में भी भाग लेंगे। फिर चुनाव के बाद भी हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जिन्दाबाद!
इंकलाब जिन्दाबाद!
मार्क्सवाद-लेनिनवाद शिवदास घोष
विचार जिन्दाबाद!
सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद जिन्दाबाद!

सूत्र:

1. ''भारत के करोड़ों बेबस लोग रोटी मांग रहे हैं ...और हम उन्हें पत्थर दे रहे हैं। भूखे लोगों को धर्म सिखाना ... उनका अपमान करने जैसा है।'' (विवेकानन्द की रचनाएं)

2. ''जीवंत ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, तथापि तुम मंदिर, गिर्जाघर का निर्माण कर रहे हो और हर प्रकार की काल्पनिक मिथ्या वस्तु में यकीन कर रहे हो। मानव आत्मा या मानव शरीर ही एकमात्र उपासना योग्य ईश्वर है। ... मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ... उस मंदिर के अंदर ताजमहल है।'' (विवेकानन्द की रचनाएं, भाग-2)

3. ''अगर मेरा कोई बेटा होता, तो वह बड़ा होकर ईसा मसीह बन सकता था, बुद्ध बन सकता था, मोहम्मद बन सकता था। वह जो बनना चाहता, बन सकता था। ... यह बहुत स्वाभाविक है कि एक ही साथ पूरी आजादी का उपभोग करते हुए और बिना किसी संघर्ष के मेरा बेटा बौद्ध बन सकता है, मेरी पत्नी ईसाई बन सकती है और मैं खुद मुसलमान बन सकता हूं। इसमें नुकसान कहां है? (विवेकानन्द की रचनाएं, भाग-3, पांचवां संस्करण)

4. ''हम मानव जाति को वहां ले जाना चाहते हैं, जहां न वेद होगा, न बाइबिल होगी और न ही कुरान होगी। लेकिन सभी काम वेद, बाइबिल और कुरान के समन्वय से होंगे। ... (विवेकानन्द की रचनाएं, भाग-1)

5. ''सभी धर्मों को सत्य मानकर अपनाना केवल परधर्म सहिष्णुता नहीं - यही हम प्रचार करते हैं और कार्य में भी परिणत करते हैं। विशेष सावधान, किसी का क्षुद्रतम अधिकार भी कुचलो नहीं।'' (विवेकानन्द की रचनाएं, भाग-7)

6. ''भौगोलिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत और साझे खतरे ने, जिसने हमारे राष्ट्र की अवधारणा को तैयार किया है, हमें अपने सही हिन्दू राष्ट्रवाद की सकारात्मक और प्रेरक सामग्री से वंचित कर दिया है और अनेक 'स्वतंत्रता आंदोलनो' को वस्तुत: ब्रिटिश-विरोधी आंदोलनों में तब्दील कर दिया है। ब्रिटिश-विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पर्याय समझा जा रहा है। इस प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण ने समग्र स्वतंत्रता आंदोलन पर, उसके नेतृवर्ग और आम लोगों पर विनाशकारी प्रभाव डाला था।'' –गोलवलकर (हम और हमारी राष्ट्रीयता परिभाषित)

7. ''भारत जैसे उपनिवेशों के जीवन की परिस्थितियों की एक मौलिक और नयी विशेषता केवल यही नहीं कि यह राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग क्रांतिकारी धड़े और समझौतावादी धड़े में बंट गया है बल्कि मुख्यत: इस बुर्जुआ वर्ग के समझौतावादी धड़े ने पहले ही साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ कर ली है। साम्राज्यवादियों के मुकाबले क्रांति से ज्यादा डरने वाले और अपने देश के बजाय अपनी तिजोरियों से ज्यादा सरोकार रखने वाले इस बुर्जुआ वर्ग का यह समझौतापरस्त धड़ा पूरी तरह क्रांति के घोर दुश्मनों के खेमे में जा रहा है, यह अपने ही देश के मजदूरों और किसानों के खिलाफ साम्राज्यवादियों के साथ गठजोड़ कर रहा है। ... शहर और गांव की पेटी बुर्जुआ जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व देने के लिए राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के समझौतापरस्त धड़े को विच्छिन्न करने के बाद बुर्जुआ वर्ग के क्रांतिकारी धड़े के साथ अवश्य ही कम्युनिस्ट पार्टी खुलेआम गठजोड़ कर सकती है और वह करना ही होगा।।'' –जे वी स्टालिन

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-2020
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

आशा, मिड-डे मील, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं से एआईयूटीयूसी का आह्वान

28 जनवरी, 2019 को प्रातः 11 बजे दिल्ली संसद चलो

63 लाख महिला कामगारों–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं, आशा तथा मिड-डे मील कार्यकर्ताओं का हम पुरजोर आह्वान करते हैं कि नारीत्व के अपमान व अनादर के खिलाफ आप एकजुट होकर उठ खड़ी हों और सम्मान और मान-मर्यादा की खातिर लगातार चलाये जा रहे अपने आंदोलन को तेज करने के लिए 28 जनवरी, 2019 को दिल्ली में संसद पर होने जा रहे अखिल भारतीय विशाल प्रदर्शन में आप सभी हजारों की संख्या में शामिल हों।

स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, तब तक 'वॉलंटियर' की बजाय श्रमिक का दर्जा देने, मानदेय के स्थान पर वेतन देने, न्यूनतम वेतन हर महीना 21000 रुपये देने के साथ महंगाई भत्ता, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, प्रसूति लाभ लागू करने और प्रतिमाह 6000 रुपये पेन्शन देने, बजट राशि बढ़ाने और निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाने के अलावा तीनों स्कीमों में सुधार लाने जैसी मांगें लम्बे अरसे से लटकाई जा रही हैं।

यह बात आपको मालूम है कि कक्षा आठ तक के लगभग 19 करोड़ बच्चों की देखभाल के साथ-साथ केंद्र द्वारा चलाई जा रही आईसीडीएस, एनएचएम तथा एमडीएम की इन तीनों अति महत्वपूर्ण स्कीमों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा अनेक कष्टों और कठिनाइयों को झेलते हुए दशकों से आप करोड़ों बच्चों एवं माताओं की सेवा करती आ रही हैं।

स्कीम वर्करों की हमारी यूनियनें और फेडरेशनें तीनों स्कीमों में सेवा शर्तों में सुधार के लिए लम्बे अरसे से संघर्ष करती आ रही हैं। उपरोक्त मांगों को हासिल करने के मद्देनजर एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध विभिन्न यूनियनों ने केंद्र व राज्य स्तर पर अलग से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए हैं। बहुत से राज्यों में आंदोलन तेज हुये हैं।

एआईयूटीयूसी ने अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर सर्वोच्च त्रिपक्षीय बॉडी भारतीय श्रम सम्मलेन (आई एल सी) के मंच से निरंतर कई सत्रों में इन जायज मांगों को उठाया था। परिणामतः आईएलसी के 45वें सत्र में सर्वसम्मत राय से यह आम सहमति बनी थी कि स्कीम वर्करों को 'वॉलंटियरों' की बजाय श्रमिकों का दर्जा दिया जाएगा और मानदेय या प्रोत्साहन राशि की बजाय न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। साथ ही उन्हें पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों के तहत लाया जायेगा। यह फैसला 2013 में लिया गया था। तब से पांच वर्ष बीत चुके हैं। न तो कांग्रेस सरकार ने और न ही बीजेपी सरकार ने इस वायदे को लागू किया है।

बहुत दबाव डालने पर 19 जनवरी, 2017 को एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें श्रम मंत्रालय ने बताया था कि स्कीम वर्करों को पीएफ और ईएसआई स्कीम के तहत लाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। लेकिन इस बारे सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इसके प्रतिवाद में एआईयूटीयूसी सहित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 17 जनवरी, 2018 को एक दिवसीय देशव्यापी सफल हड़ताल की गई थी। दूसरी तरफ, 2014 में सत्तासीन हुई बीजेपी ने मेहनताना बढ़ाने की वर्षों से उठाई जा रही अति जरूरी मांग पर कतई कोई ध्यान नहीं दिया।

इसके विपरीत इन्होंने बजट राशि घटा दी, इन स्कीमों के महत्व को घटा दिया और इस सामाजिक क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों के इस रवैये से देश के कोने-कोने में स्कीम वर्करों में गहरा रोष-आक्रोश है।

इस बात को भांपकर कि हालात खतरनाक बन सकते हैं, आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सितंबर, 2018 में प्रधानमंत्री ने प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 1500 रुपए व आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 750 रुपए महीना की बढ़ोतरी के साथ-साथ आशा कार्यकर्ताओं के लिए कंपनसेशन पैकेज अर्थात इंसेंटिव दोगुना करने की घोषणा की थी लेकिन उनके फिक्स मेहनताने में मासिक बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की गई। जबकि मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया। राज्य सरकारों की तरह केंद्र सरकार ने भी उनसे यह सौतेला बर्ताव किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी व आशा के बारे की गयी घोषणा आज तक लागू नहीं की गई है और दूसरी तरफ, राज्य सरकारों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बढ़ोतरी के 40 प्रतिशत का भुगतान केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें करना है, इसलिए राज्यों के द्वारा अदा किए जाने वाले या अदा किये जा रहे अतिरिक्त मानदेय में आनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी। जिन राज्यों ने अतिरिक्त मानदेय बढ़ाने का पहले आश्वासन दिया था, वे अब यह कह रहे हैं कि यह वृद्धि लागू नहीं की जा सकेगी क्योंकि उन्हें केंद्र की बढ़ोतरी राशि का भी भुगतान करना पड़ेगा।

असल में, यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई धोखेबाजी का मामला है। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों में कई महीनों से मानदेय तक का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, कई महीनों से आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरक पोषाहार सामाग्री सप्लाई नहीं की गयी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कहा जा रहा है कि वे इस पोषाहार सामग्री को अपने पैसे से खरीदें और आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े बच्चों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को खिलाएं।

इस बदहाल पृष्ठभूमि में स्कीम वर्करों –मिड-डे मील, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से एआईयूटीयूसी अपील करता है कि वे जमीनी स्तर पर अपनी-अपनी कमेटियों का गठन करें और साथ ही सभी जगह साझी कमेटियां भी बनायें ताकि स्कीम वर्करों की शिकायतों सहित लंबे अरसे से लंबित मांगपत्र को मनवाने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों द्वारा 8 और 9 जनवरी, 2019 को आहूत दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाया जा सके। इसी की निरंतरता में एआईयूटीयूसी तीनों स्कीमों में कार्यरत लाखों कामगार महिलाओं का आह्वान करता है कि वे लगातार जारी अपने आंदोलन को और भी तेज करने तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए 28 जनवरी, 2019 को हजारों की संख्या में दिल्ली संसद मार्ग पर प्रदर्शन में शामिल हों।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड वी. एन. सिंह नहीं रहे

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड वी. एन. सिंह ने जौनपुर जिले के बदलापुर में अपने निजी आवास पर 4 दिसंबर 2018 को अंतिम सांस ली। वे लंबे अर्से से बीमार चल रहे थे।

कॉमरेड वी. एन. सिंह 90 साल के थे। देहांत की खबर मिलते ही राज्य के कानपुर स्थित प्रांतीय कार्यालय सहित विभिन्न जिला कार्यालयों में लाल झंडा झुका दिया गया। उनका पार्थिव शरीर बदलापुर कार्यालय में पहुंचने पर राज्य सचिव कॉमरेड पुष्पेंद्र सहित अन्य राज्य कमेटी सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में वे तत्कालीन बिहार राज्य सांगठनिक कमेटी के भी सदस्य रहे। बिहार राज्य कार्यालय पटना में भी लाल झंडा झुका दिया गया।

कॉमरेड वी. एन. सिंह शुरुआती जीवन में रेलवे में नौकरी करते थे। उस दौरान ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ उनका जुड़ाव हुआ। वे विभिन्न वामदलों के आला नेताओं के संपर्क में आये। कुछ दिनों के लिए वे नक्सलपंथी राजनीति के भी प्रभाव में आये। इसी दौरान उन्होंने एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव तथा इस युग के प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक व दार्शनिक कॉमरेड शिवदास घोष का नाम सुना। वे कोलकाता गये और कॉमरेड शिवदास घोष को ढूंढकर उनसे मिले।

कॉमरेड वी. एन. सिंह 1969 में कॉमरेड शिवदास घोष से पहली बार मिले। कॉमरेड शिवदास घोष के सानिध्य में आकर उनके जीवन की दिशा ही बदल गयी। कॉमरेड शिवदास घोष के पथ-प्रदर्शन तथा स्नेह-प्यार के आधार पर वे धीरे-धीरे कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और जननेता में तब्दील हुए। उत्तर प्रदेश में पार्टी काम-काज की शुरुआत उन्हीं के द्वारा हुई। बाद में लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद सहित करीब 14 जिलों में पार्टी गतिविधियों का विस्तार हुआ। महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष भी कई बार उत्तर प्रदेश गये थे। उत्तर प्रदेश के अनेक कॉमरेडों को वे कॉमरेड शिवदास घोष से मिलवाया करते थे और उन्हीं के निर्देशानुसार उनका निर्माण करने की कोशिश किया करते थे। वे कॉमरेड शिवदास घोष को हमेशा याद किया करते थे, यहां तक कि जब वे बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़े थे, तब भी उनके दिल में कॉमरेड शिवदास घोष की यादें देदीप्यमान थीं। कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा मिले स्नेह-प्यार की चर्चा वे जीवन के अंतिम दिनों में भी किया करते थे। ऐसा करते हुए उनकी आंखें नम हो जाया करती थीं।

कॉमरेड वी. एन. सिंह में अदम्य साहस था। उन्होंने अनेकों जन आंदोलनों का नेतृत्व दिया। गरीबों पर जुल्म होते देखकर वे उसके खिलाफ संघर्ष में कूद पड़ते थे। जन आंदोलनों के निर्माण के लिए वे राज्य के विभिन्न स्थानों का दौरा किया करते थे। उनकी पहलकदमी और आंदोलन में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका की वजह से ही विभिन्न जिलों में पार्टी संगठन का निर्माण हुआ। पार्टी में काफी कार्यकर्ता-संगठनकर्ता शामिल हुए। आंदोलन के दौरान वे कई बार पुलिस जुल्म के भी शिकार हुए। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।

अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत में बिहार के डेहरी ऑन सोन में नौकरी करने के दौरान उन्होंने रोहतास तथा औरंगाबाद जिलों में भी पार्टी संगठन का निर्माण किया। पार्टी के मजदूर संगठन एआईयूटीयूसी की अखिल भारतीय कमेटी के वे उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। 1974 में अखिल भारतीय रेल हड़ताल हुई थी। इस हड़ताल में सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। वे तीन महीने तक जेल में रहे। उन्हें सेवा से निलंबित भी किया गया। वे किसान संगठन ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय नेता भी थे।

कई साल पहले वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। वे राज्य सचिव की जिम्मेदारी निभाने में शारीरिक रूप से पूरी तरह असमर्थ हो गये। उनकी सलाह तथा पार्टी की केंद्रीय कमेटी के अनुमोदन पर 2017 में आयोजित उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन में कॉमरेड पुष्पेंद्र को राज्य सचिव चुनते हुए नयी राज्य सांगठनिक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में वे एक सदस्य के तौर पर थे। जब तक संभव हो सका, वे पार्टी की पत्र-पत्रिकाओं का नियमित अध्ययन करते रहे, नेताओं और कार्यकर्ताओं को तरह-तरह की सलाह देते रहे और साथ ही वे विभिन्न तरह की सूचनाएं भी रखा करते थे।

कॉमरेड वी. एन. सिंह के निधन से पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। उनका क्रांतिकारी जीवन हम सबके के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करता रहेगा।

कॉमरेड वी. एन. सिंह लाल सलाम!

फ्रांस की जनता बहादुरी से लड़ी, दुनिया के लोगों के लिए मिसाल पेश की

(पृष्ठ 1 का शेष)

शहरों की सड़कों पर सैलाब की तरह फैल गए थे और जीवन की रफ्तार रोक दी थी। अपने रास्ते में उन्हें पुलिस के साथ जमकर लड़ाई लड़नी पड़ी। पुलिस ने रबड़ की गोलियों, पानी की बौछारों, आंसू गैस के गोलों, बख्तरबंद गाड़ियों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। देश के राष्ट्रपति ने निरंकुशता पूर्वक दहाड़ते हुए कहा कि 'उपद्रवियों के उपद्रव के सामने सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी', उन्हीं की अगुवाई में सरकार ने मिलिट्री तैनात करने और आपातकाल लागू करने तक की धमकी दे डाली। लेकिन फ्रांस के बहादुर लोगों को झुकाया नहीं जा सका। हजारों घायलों का खून सड़कों पर बहा; एक 80 साल की वृद्ध महिला और एक नौजवान की घायल अवस्था में मृत्यु हो गई। हजारों को जेल में ठूंस दिया गया। इन अत्याचारों और दमन के बावजूद संघर्षरत फ्रेंच लोग अडिग खड़े रहे। उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज बुलंद की कि वह 1% अमीरों, कारपोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधि है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांसीसी लोगों ने नारा बुलंद किया : पूंजीवाद मुर्दाबाद!

फ्रांस के लोग जिन्होंने एक समय बुर्जुआ डेमोक्रेसी को जन्म दिया था, अब अपनी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इस प्रकार अपनी आवाज उठा रहे थे। जीवन के कटु अनुभव से अब उनकी समझ में आ रहा है कि उदारतावाद, कलात्मकता और बौद्धिकता की बड़ी-बड़ी तमाम बातों के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि उनका देश एक पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश है जिस के लोगों को संकटग्रस्त विश्व व्यवस्था के सड़ते हुए दलदल में फेंक दिया गया है जहां उन्हें साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के नुस्खे के मुताबिक घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश दुनिया की चंद आणविक शक्तियों में से एक बन गया है लेकिन यह उन्हें रोजमर्रा की परेशानियों से निजात दिलाने में नाकाम रहा है। इसके बजाय पूंजीवादी शासकों ने अपनी संकटग्रस्त व्यवस्था का सारा बोझ लोगों के कंधों पर लाद दिया है। इंधन तेल की कीमतों में वृद्धि नवीनतम है जिसे पर्यावरण बचाने और ऐसे ही अन्य बहानों की आड़ में किया गया है। इसने क्रूर, हृदयहीन जालिम शासकों यानी एकाधिकारी पूंजीपतियों और उनके कारपोरेट घरानों के खिलाफ आम लोगों में एक बार फिर एकजुटता और दृढ़ता के साथ उठ खड़े होने का साहस भर दिया। फिलहाल आक्रोशित लोगों ने शुरुआत में उपेक्षापूर्ण राष्ट्रपति को पीछे हटने और इंधन तेल की कीमतों में वृद्धि वापस लेने, लोगों को सार्वजनिक रूप से संबोधित करने तथा अन्य रियायतें घोषित करने के लिए बाध्य कर दिया। हेंकड़ी को जनशक्ति के सामने झुकना पड़ा; जन आंदोलन तयशुदा बातों को पलटवा सका।

वीरोचित फ्रांस ने एक बार फिर आंदोलन के आह्वान के साथ दुनिया को प्रेरित कर दिया। इन दिनों में जब आधुनिक संशोधनवाद ने अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है लोगों का यह संघर्ष एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करता है। आंदोलन की लहरें सरहदों के पार जा रही हैं उदाहरण के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, नीदरलैंड के एक शहर रोटेडम तक पहुंच गई हैं। सिर्फ फ्रांस के एकाधिकारी पूंजीपतियों की ही नहीं, बल्कि अन्य देशों के पूंजीपतियों-साम्राज्यवादियों की भी रातों की नींद हराम हो गई है। अब तक पूंजीवाद-साम्राज्यवाद का अभेद्य गढ़ समझे जाने वाले अमेरिका में महीना भर चला 'वॉल स्ट्रीट दखल करो' आंदोलन हो, इस धरती पर तेल से भरपूर भूभाग जिसे अकूत मुनाफे के लिए खुली शिकारगाह के रूप में निशाना बनाया गया उस मध्यपूर्व और उत्तरी अफ्रीका में उठने वाली 'अरब स्प्रींग' नामक बगावत हो या लोगों पर अपने संकट का तमाम बोझ लादने के लिए सरकारों द्वारा उठाए गए तथाकथित मितव्ययिता कदमों के खिलाफ या यूरोपियन यूनियन से संबद्ध रहने के सवाल पर ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, स्कॉटलैंड यहां तक कि अधिक विकसित देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में जनआंदोलनों की लहर हों, इन सब का डरावना तजुर्बा अभी भी उनके ज़ेहन में है।

इसलिए फ्रांस में इस आन्दोलन को एकाधिकारी पूंजीपति अपने लिए घोर अपशकुन मान रहे हैं। इसने एक बार फिर संदेहातीत रूप से स्पष्ट कर दिया है कि झांसे भरे वादों से लोगों को लुभाने और इस प्रकार उन्हें संसदीय राजनीति की चारदीवारी तक महदूद रखने के तमाम प्रयासों के बावजूद शासक पूंजीपति वर्ग शोषित-पीड़ित मेहनतकश लोगों को आंदोलन में शरीक होने से रोक नहीं पा रहा है जिनमें यहां तक कि इस व्यवस्था के खिलाफ आह्वान तक भी किए जा रहे हैं। यह सच्चाई है जिसे पूंजीवादी-साम्राज्यवादी नकार नहीं सकते हैं।

फ्रांस सहित दुनिया के संघर्षरत लोगों को एक और सच्चाई पर ध्यान देना होगा। निस्संदेह इन आंदोलनों में शोषित-पीड़ित मेहनतकश लोग बहादुरी से शामिल हुए हैं जो कि लोगों के सामने असल दुश्मन पूंजीवाद के खिलाफ नारे लगाते हुए बगावत का रूप भी ले रहे हैं। यह अमेरिका या अन्य जगहों हुआ और अब फ्रांस में हो रहा है। तमाम मामलों में लोग गुस्से से फट पड़े हैं, उन्होंने हमले और कठिनाइयां झेली हैं, वे क्रूर पूंजीवादी शासन तंत्रों के खिलाफ लड़े हैं। यह सच है कि हाल फिलहाल के लिए वे अपने पूंजीवादी शासकों के होश उड़ा पाये थे और कुछ मांगें हासिल कर सके थे लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। लेकिन जब इन शासन तंत्रों के खिलाफ एक सतत संगठित आंदोलन विकसित करने का सवाल उठता है, तो यह पूरी तरह से एक अलग मुद्दा हो जाता है। जो शासन तंत्र पूरी तरह से रेजीमेंटेड है, घातक रूप से अस्त्र-शस्त्रों से लैस है और जो उन्हें चुनौती देने या उखाड़ फेंकने का साहस करेगा, उस किसी का भी पाशविक रूप से, सुनियोजित ढंग से कत्ल तक कर सकते हैं। बेरहम पूंजीवादी शोषण सहन न कर पाने की वजह से लोग परिवर्तन के लिए, क्रान्ति के लिए पुकार कर सकते हैं लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन फिर भी दूर की बात रह जाती है। फ्रांस के लोग अभी भी लड़ रहे हैं। उन्होंने संगठित होने का प्रयास किया है लेकिन वे प्रारंभिक अवस्था में है, क्रांति के लिए दीर्घकालिक संगठित संघर्ष की खातिर निश्चित ही एक मजबूत सैद्धांतिक-सांगठनिक नेतृत्व की जरूरत होगी। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव और इस युग के अन्यतम श्रेष्ठ मार्क्सवादी चिंतनकार कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा है कि ''समाज में किसान-मजदूरों-शोषित लोगों के असंतोष को लेकर क्रान्ति बार-बार लहर पर लहर उठकर सैलाब लाने की कोशिश करेगी। लहर पर लहर उमड़-घुमड़ कर यह फूट पड़ना चाहेगी। समाज में द्वंद्व पहले से भी कई गुना घनघोर और तेजतर होकर इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने की पुकार करेगा। यह हमारे जमीर को झकझोरेगा, यह मानवजाति से अपील करेगा कि क्रान्ति चाहिए। फिर भी क्रान्ति नहीं आएगी, वह बार-बार वापिस लौट जाएगी, वह विपथगामी हो जाएगी और उससे बार-बार प्रतिक्रिया को ही फायदा पहुंचेगा – क्रान्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि क्रान्ति का नेतृत्व करने लायक शक्ति को लिए हुए क्रान्तिकारी पार्टी का आविर्भाव नहीं होगा।'' (एक क्रान्तिकारी के प्रति श्रद्धांजलि, 17 सितम्बर, 1974 का भाषण,, सेलेक्टिड वर्क्स, वोल्यूम 3, अंग्रेजी संस्करण,, पृष्ठ 390) क्रांति के लिए एक सही नेतृत्व के महत्व को इस तरह रेखांकित करते हुए कॉमरेड शिवदास घोष ने यह भी दर्शाया है कि परिवर्तन के लिए लोग लालायित होते हैं, जोरदार विशाल प्रदर्शनों का साहस करते हैं, उन सब शोषित-पीड़ित लोगों के व्यापक तबकों को शामिल कराते हुए जीवंत जनवादी आंदोलन करते हैं, तो शासक पूंजीपति वर्ग, एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग इनको गुमराह करने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाते हैं। वे रियायतें देकर, वादों की घोषणा करके चालबाजी करते हैं। लम्बे अर्से की बात करें तो उफान चाहे कितना भी मजबूत रहा हो, लोगों ने चाहे जितनी भी दुख-तकलीफें झेली हों यदि उनको सही तरह से मार्गदर्शन देने वाला नेतृत्व नहीं रहे, तो पूंजीवाद द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को जरा छूने तक में नाकाम रहेगा। इससे लोगों में निराशा-हताशा पैदा होती है। वे आंदोलन से विमुख हो जाते हैं। शोषण-उत्पीड़न न सह पाने की वजह से साहस के साथ दुबारा उठ खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर से उसी हताशा-निराशा का सामना करना पड़ता है। यह तब तक जारी रहता है जब तक की क्रांतिकारी नेतृत्व आंदोलन की अगुवाई के लिए आगे नहीं आ जाता।

इन सब से भी बढ़कर, मरणासन्न पूंजीवाद के इस युग में जब शोषणमूलक दमनात्मक पूंजीवाद हर संभव तरीके से लोगों को लूट रहा है और उन्हें धोखा दे रहा है। ऐसे में, यह अत्यंत जरूरी हो जाता है कि पूंजीवादी देशों में व्यापक जोरदार संगठित जनवादी आंदोलन गठित किये जाएं। फ्रांस में लोगों द्वारा छेड़ा गया हाल का बहादुराना संघर्ष इस मामले में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो दुनिया के मेहनतकश लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। हम एक बार फिर उन्हें सलाम करते हैं। साथ ही साथ हम इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि मुक्ति के वांछित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आंदोलनों को सही क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व की जरूरत होती है। इसलिए हर एक मामले में मौजूदा समय की समस्याओं को हल करने और उनके असर को दूर करने के लिए एक उन्नत नई समझदारी के आधार पर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ेगी जो समझदारी क्रांतिकारी सिद्धांत और संस्कृति पर आधारित होगी। आधुनिक संशोधनवाद के घातक प्रभाव के खिलाफ सतत संघर्ष छेड़े बिना आज ऐसी एक पार्टी बनायी नहीं जा सकती है। इस संघर्ष के सारतत्व में शामिल है नए तरह के अर्थवाद और सामाजिक व्यक्तिवाद के खिलाफ संघर्ष जिसे महान मार्क्सवादी नेता कॉमरेड शिवदास घोष ने क्रान्तिकारी आंदोलन विकसित करने के रास्ते में पैदा हुए भयंकर खतरे के रूप में चिन्हित किया है। क्रांति के रास्ते से इन व्याधियों का उन्मूलन करने के लिए जरूरी है व्यक्तिगत स्वार्थ को सामाजिक स्वार्थ के साथ एकात्म कर देना जो सही क्रांतिकारी चरित्र का मापदंड है। साथ ही साथ सही क्रांतिकारी पार्टी के विकास में मददगार होने का भी एकमात्र रास्ता है और इस तरह जन आंदोलन को इसकी वांछित मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। हालात मांग करते हैं कि दुनिया भर के संघर्षरत लोग फ्रांस के बहादुर लोग गंभीरतापूर्वक इन मुद्दों पर गौर करें जिन्हें फ्रांस के हालिया शानदार संघर्ष ने अपने पीछे छोड़ा है।

आंगनबाड़ी कर्मियों ने दिया धरना

लखनऊ (उ.प्र.) :

उ.प्र. विधान सभा आम चुनाव 2017 से पहले तथा अब प्रचंड बहुमत से सत्तासीन भाजपा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के अन्य लोगों के साथ-साथ आँगनबाड़ी कर्मचारियों से अनेक वादे किए थे। जैसे यदि उनकी सरकार बनी तो वे आँगनबाड़ियों की तस्वीर बदल देंगे, सरकार बनने के 120 दिन के अंदर-अंदर उनके मानदेय मे बढ़ोतरी कर देंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद भी जब कोई भी वादा पूरा नही किया गया, तो एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसियेशन ने 27 अक्तूबर को लखनऊ में रैली कर 'योगी सरकार वादा निभाओ' आन्दोलन की प्रदेश में शुरुवात की।

जिलों पर धरने, प्रर्दशन, सम्मेलन आदि करते हुए 1 व 2 अक्टूबर को लखनऊ में दो दिवसीय रैली की और इको गार्डन लखनऊ में दो दिवसीय धरना दिया। अनेक बाधाओं को पार करते हुए 20 जिलों से आयीं लगभग 5000 आँगनबाड़ी कर्मियों ने जोरदार धरना-प्रर्दशन किया तथा सरकार से तत्काल वादे पूरे करने की मांग की।

धरने को संबोधित करते हुए आँगनबाड़ी एम्लाइज फैडरेशन ऑफ इंडिया (एफी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चाहल ने कहा कि चुनाव के समय वादे करना तथा फिर भूल जाना यह हर चुनावी पार्टी की पुरानी आदत है।

उन्होंने कहा कि आगामी 28 जनवरी 2019 को वर्तमान मोदी सरकार के आखिरी बजट सत्र से दो दिन पहले स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम 18000 रु० मासिक वेतन, पेंशन आदि माँगों को लेकर देश की सभी स्कीम वर्करों (आँगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील आदि) का एक विशाल संसद मार्च होगा। सभी इसकी तैयारी में जुट जाएँ।

लखनऊ में धरने को प्रदेश महासचिव शशि बाला, उपाध्यक्ष सरिता शाक्य, हीरावती तथा मिथलेश चौधरी, विनीता अग्निहोत्री, पूनम विश्नोई, ओमवती गंगवार, ममता मिश्रा, सत्यबाला चौधरी, रजनी दिवाकर, स्नेहलता आदि ने संबोधित किया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7-8 and 22-23 of every month, Fortnightly, Date of Publication : December 20, 2018

6 दिसंबर – बाबरी मस्जिद तोड़े जाने का दिन 'सांप्रदायिकता–विरोधी दिवस' के रूप में मनाया गया

दिल्ली : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. प्राण शर्मा

दिल्ली :

संघ परिवार द्वारा बाबरी मस्जिद के ऐतिहासिक स्मारक को ध्वस्त करने की 26वीं बरसी 'सांप्रदायिकता–विरोधी दिवस' के रूप में मनाने के हमारी पार्टी एसयूसीआई (सी) के आह्वान पर दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी ने 6 दिसंबर को संसद मार्ग, नई दिल्ली में एक दिवसीय धरना दिया। धरने को एसयूसीआई (सी) की हरियाणा राज्य कमेटी के तीन सदस्यों, मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्राण शर्मा और जनसंगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। पार्टी की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड रमेश शर्मा ने मंच संचालन किया।

कॉमरेड प्राण शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का एक विकृत विचार प्रस्तुत किया जो 'सर्व धर्म सम्भाव' को मानता है। उन्होंने कहा कि इस विकृत विचार की जड़ें गांधीजी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता आंदोलन में थीं, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न धर्मावलम्बियों का तुष्टिकरण किया। 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के साथ, भारत वास्तव में बहु-धर्मीय राज्य बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ नेताजी सुभाषचंद्र बोस और शहीद-ए-आजम भगत सिंह का दृष्टिकोण पूरी तरह अलग था क्योंकि वे सही धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे और इस पर अमल करते थे, जिसका मतलब था कि धर्म को राजनीति से अलग करना और धर्म को व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले के रूप में मानना। इस दृष्टिकोण से धर्म, जाति, पंथ और रंग के आधार पर लोगों में फूट डालने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी होती। लेकिन समझौते से भारतीय पूंजीपति वर्ग को राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ।

उन्होंने इंगित किया कि आज पूंजीवाद के गहन और न हल होने वाले संकट में, भारतीय पूंजीपति वर्ग की दोनों भरोसेमंद पार्टियां–बीजेपी और कांग्रेस लोगों में फूट डालने और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाकर नकली मुद्दों की तरफ फेरने के एक ही उद्देश्य से बहुसंख्यक समुदाय, यानी हिंदुओं के धार्मिक कट्टरपंन और अंधराष्ट्रवाद को उकसा रही हैं। उन्होंने कहा, कि 16वीं सदी के ऐतिहासिक स्मारक बाबरी मस्जिद को तोड़ने की दोषी कांग्रेस और बीजेपी दोनों थी। 1992 में केंद्र में सत्ता में थीं कांग्रेस और यूपी राज्य (जहां बाबरी मस्जिद स्थापित थी) भाजपा शासन में थी। उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे 1948 से इन दोनों पार्टियों–बीजेपी (जिसे पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था) और कांग्रेस ने चुनावी लाभ बटोरने और इस प्रकार पूंजीवादी शासन को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू अंधराष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया।

ऐसी स्थिति के तहत, जब भारतीय संविधान (यानी सर्व धर्म सम्भाव') में धर्मनिरपेक्षता की विकृत अवधारणा का खुलासा करना आवश्यक था, जिसका उपयोग बुर्जुआ वर्ग द्वारा उनके अपने लाभ के लिए किया जा रहा है, पांच वामपंथी पार्टियों–सीपीआई(एम), सीपीआई, सीपीआई (एमएल) -लिबरेशन, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने 6 दिसंबर को 'संविधान बचाओ-धर्मनिरपेक्षता दिवस' के रूप में मनाने का आह्वान किया, जिस पर हम सहमत नहीं हो सके। इसलिए हमारी पार्टी ने सांप्रदायिकता-विरोधी दिवस के रूप में उनसे अलग मनाया। बाबरी मस्जिद को अपने मूल आकार में बहाल करने और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग के साथ धरना समाप्त हुआ।

पटना (बिहार) : ऐतिहासिक स्मारक बाबरी मस्जिद की 26वीं बरसी पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी के तत्वावधान में सांप्रदायिकता-विरोधी मार्च निकाला गया। मार्च गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से निकलकर भगत सिंह चौक तक गया। मार्च में शामिल लोग हाथों में रंग-बिरंगी तख्तियां लिए हुए थे। इन पर सांप्रदायिक व जातिवादी उन्माद फैलाकर वोट की राजनीति करने, लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने और सामाजिक ताने-बाने को क्षतविक्षत कर भातृघाती दंगों में समाज को झोंक देने की घृणित साजिश का विरोध किया गया था। सांप्रदायिकता-विरोधी मार्च में शामिल लोग सांप्रदायिक सौहार्द के प्रसंग में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद तथा महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस के कथन तख्तियों पर लिखे हुए थे। सांप्रदायिकता-विरोधी मार्च भगत सिंह चौक पर आकर सभा में तब्दील हो गया।

वहां आयोजित संक्षिप्त सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला सचिव कॉ. साधना मिश्रा ने कहा कि शासक पूंजीपति वर्ग की भरोसेमंद पार्टियां आज जितना ही मंदिर-मस्जिद, जात-पात और क्षेत्रीयता-प्रादेशिकता के भंवर में जनता को फंसा रही हैं, उतना ही बड़े पूंजीपतियों-उद्योगपतियों को करोड़ों रुपयों की छूट दे रही हैं, हजारों करोड़ रुपयों के उनके बैंक के कर्ज माफ कर रही हैं और हजारों करोड़ रुपए लूटकर कर विदेश भागने का भी प्रबंध कर रही हैं। साथ ही बेरोजगारी शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली का दंश झेल रही देश की जनता पर नेता-मंत्रियों के भ्रष्टाचार और लूट की मार जनता को तबाह कर रही है। ऐसे में लुटेरों की मददगार सरकार केंद्र में सत्तासीन भाजपा और सत्ता में वापसी के लिए बेचैन कांग्रेस, दोनों ही जनता की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर चुनावी फायदे के लिए धर्म और जात-पात का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। उग्र हिंदुत्व और नरम हिंदुत्व का परचम लेकर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच इस बात की एक नयी होड़ लगी है कि कौन कितने मंदिरों में जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक नफरत और साम्प्रदायिक गतिविधियों को फैलाने में भाजपा आज सबसे आगे है। हिंदू-मुसलमानों के बीच विरोध को तेज करने के उद्देश्य से बाबरी मस्जिद-राम मंदिर, असम में एनआरसी के नाम पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को विदेशी बताना तथा हिंदू धर्म के ही अंतर्गत दलितों और सवर्णों के बीच नफरत पैदा करने तथा दलितों पर हमले जारी हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जन जीवन के ज्वलंत सवालों पर जन आंदोलन विकसित करने का आह्वान किया।

सभा को जिला कमेटी सदस्य कॉ. सूर्यकर जितेंद्र, कॉ. राजकुमार चौधरी, एआईडीएसओ राज्य सचिव कॉ. रोशन कुमार रवि ने भी संबोधित किया।

'मी टू' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन

दिल्ली : ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2018 , को 'मी टू' विषय पर संगोष्ठी की गई। इसमें विभिन्न इलाकों से आई छात्राओं व महिलाओं ने हिस्सा लिया और महिलाओं बच्चियों पर बढ़ते अपराधों तथा वर्तमान में चल रहे विश्वव्यापी 'मी टू' आंदोलन के समर्थन में अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में एआईएमएसएस की राज्य अध्यक्ष प्रोफेसर सुबोध शर्मा, सचिव ऋतु कौशिक, उपाध्यक्ष नीतू खन्ना, एडवोकेट सुमिता बानो, शारदा दीक्षित, आशा रानी, सुमन यादव, संध्या विश्वकर्मा तथा सुनिधि शर्मा ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे एसयूसीआई(सी) के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्राण शर्मा।

वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में चल रहे 'मी टू' आंदोलन ने महिलाओं को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को व्यक्त करने का एक प्लेटफार्म प्रदान किया है। इसके कारण समाज में प्रतिष्ठित पदों पर आसीन राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, फिल्म कलाकारों द्वारा महिलाओं से किए गए दुर्व्यवहार सामने आये हैं। महिलाओं पर बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण समाज में व्याप्त पुरुषप्रधान मानसिकता है जिसके चलते महिलाओं को उपभोग की वस्तु के समान समझा जाता है तथा दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। आज 'मी टू' आंदोलन को समाज में व्याप्त पुरुष-प्रधान मानसिकता और इस मानसिकता को बढ़ावा देने वाली पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और समाजवादी व्यवस्था कायम करने के आंदोलन के रूप में गठित करने की आवश्यकता है। एकमात्र तभी महिलाओं को समानता सुरक्षा हासिल करवाई जा सकती है।

वक्ताओं ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं व महिलाओं से दिल्ली में एक मजबूत संगठन का निर्माण कर महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ रहे अपराधियों के खिलाफ एक जुझारू आंदोलन गठित करने का आह्वान किया।

खुदीराम बोस जयंती मनाई

पिलानी (राजस्थान) : एआईडीवाईओ झुन्झुनू इकाई ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस की 130वीं जयंती के अवसर पर 3 दिसंबर को वाल्मीकि बस्ती में श्रद्धांजलि सभा कर याद किया। इसकी अध्यक्षता स्थानीय निवासी विश्वनाथ लोहारा ने की थी। इस अवसर पर बच्चों ने कवितापाठ किया। एआईडीवाईओ के झुन्झुनू जिला प्रभारी कॉ. विष्णु वर्मा, एआईडीवाईओ राजस्थान के कार्यालय सचिव कॉ. सुनील कुमार और कॉमरेड दीपक दहिया ने सभा को संबोधित किया। कॉ. विष्णु वर्मा ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया। उनके अलावा, महावीर शर्मा, केदार, सुनील ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सरकार की मजदूर–कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 8–9 जनवरी 2019 को देशव्यापी हड़ताल सफल करें

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503